सूर्योदय - 06 : 26
सूर्यास्त - 05 : 44
अधिकतम तापमान 32.0° न्यूनतम तापमान 19.0°

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक
ओपन सर्च
RNI No.DELHIN/2015/66886

E-mail | opensearchdelhi@gmail.com Facebook | https://www.facebook.com/opensearch.co.in Website | www.opensearch.co.in

वर्ष : 12 अंक : 323 नई दिल्ली, बुधवार 28 अक्टूबर -2026 | नई दिल्ली, हरियाणा, बिहार से प्रकाशित | मूल्य : 02 रूपए | पृष्ठ : 08

खबरें और विज्ञापन के लिए सम्पर्क करें
Mob. : 9210092542
opensearchnews@gmail.com

नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा भारत, करना है दुनिया का नेतृत्व : मोदी

भारत भविष्य की तकनीकों को अपनाने तक सीमित नहीं, दुनिया के लिए समाधान तैयार करने का लक्ष्य : पीएम

नई दिल्ली.एजेंसी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूसरे देशों की उपलब्धियों को अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि देश का लक्ष्य भविष्य की तकनीकों का विकास करना, उनमें नवाचार को बढ़ावा देना और दुनिया की समस्याओं के समाधान तैयार करना है।

उन्होंने कहा कि भारत के युवा जिस कौशल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उनमें जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, वह उत्साह बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि दशकों पहले भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अर्थ दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ने की कोशिश करना था।

उस समय दुनिया में विकसित होने वाली तकनीक कुछ वर्षों बाद भारत पहुंचती थी और देश उसे अपनाने या उसमें सुधार करने का प्रयास करता था। हालांकि, 21वीं सदी का भारत अब नई सोच और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज भारत का लक्ष्य देश और दुनिया के लिए नई तकनीकें विकसित करना, उनकी दिशा तय करना और वैश्विक समस्याओं के समाधान देने की क्षमता हासिल करना है। भारत को भविष्य की तकनीकों को अपनाने, साहस के साथ नवाचार करने और उनके निर्माण में दुनिया का नेतृत्व करने की जरूरत है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि दशकों पहले भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अर्थ दूसरे देशों की तुलना में आगे बढ़ने की कोशिश करना था। उस समय दुनिया में विकसित होने वाली तकनीक कुछ वर्षों बाद भारत पहुंचती थी और देश उसे अपनाने या उसमें सुधार करने का प्रयास करता था

प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज देश अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल रहा है। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र तक पहुंचा, जहां इससे पहले कोई देश नहीं पहुंच पाया था। ये उपलब्धियां विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के बढ़ते सामर्थ्य और आत्मविश्वास को दर्शाती हैं। कोरोना महामारी के दौरान भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया के कई देश वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर चुनौतियों का सामना कर रहे थे, तब भारत ने अपनी वैक्सीन विकसित की। देश ने बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया और दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराई। उन्होंने इसे 21वीं सदी के भारत के आत्मविश्वास का उदाहरण बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें ज्ञान और खोज की परंपरा में रही हैं। शून्य की खोज, संख्या प्रणाली के विकास और खगोल विज्ञान में प्रगति से लेकर आज की आधुनिक तकनीकों तक, भारत अपनी वैज्ञानिक विरासत को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक तकनीक और नए आत्मविश्वास के साथ देश इस विरासत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा है।

उन्होंने परमाणु ऊर्जा के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा की जरूरत होगी। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत अपनी स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं का विकास कर रहा है। इसी दिशा में देश फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तकनीक पर काम कर रहा है।

ओम बिड़ला और थाईलैंड सीनेट अध्यक्ष मोंगकोल सुरासज्जा की मुलाकात

व्यापार, पर्यटन, रक्षा, योग समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा

नई दिल्ली.एजेंसी

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मंगलवार को नई दिल्ली में थाईलैंड की सीनेट के अध्यक्ष मोंगकोल सुरासज्जा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, रक्षा, आयुर्वेद और योग समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में दोनों पक्षों ने संसदीय सहयोग को और मजबूत बनाने, एक-दूसरे के अनुभवों और अच्छी कार्यप्रणालियों को साझा करने तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों, आपदा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मामलों में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया।

ओम बिड़ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, थाईलैंड की सीनेट के अध्यक्ष मोंगकोल सुरासज्जा से मुलाकात कर खुशी हुई। भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित गहरी मित्रता की हमने फिर से पुष्टि की। हमने व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, रक्षा, आयुर्वेद और योग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' हमारी साझेदारी को नई गति दे रही है। बिड़ला ने कहा, हमने संसदीय सहयोग को और गहरा करने, अच्छी संसदीय प्रक्रियाओं को साझा करने तथा आतंकवाद-रोधी प्रयासों, आपदा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मामलों में मिलकर काम करने के अवसरों पर भी चर्चा की। इसमें ब्रिक्स के तहत सहयोग को बढ़ाने पर भी विचार हुआ, ताकि दोनों देशों की साझा प्राथमिकताओं और लोगों के कल्याण को आगे बढ़ाया जा सके।

ओम बिड़ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, थाईलैंड की सीनेट के अध्यक्ष मोंगकोल सुरासज्जा से मुलाकात कर खुशी हुई। भारत और थाईलैंड के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों पर आधारित गहरी मित्रता की हमने फिर से पुष्टि की। हमने व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, रक्षा, आयुर्वेद और योग के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की

यह मुलाकात नई दिल्ली में संसद भवन स्थित संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित दो दिवसीय 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम के दौरान हुई। सोमवार से शुरू हुए इस फोरम में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के संसदीय नेता शामिल हुए हैं। फोरम का उद्देश्य संसदीय सहयोग को मजबूत करना और जन-केंद्रित विकास को आगे बढ़ाना है। मोंगकोल सुरासज्जा 25 अक्टूबर को 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे।

उनके स्वागत में लोकसभा ने 'एक्स' पोस्ट पर लिखा, 12वें ब्रिक्स संसदीय फोरम 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे थाईलैंड की सीनेट के अध्यक्ष मोंगकोल सुरसज्जा का हार्दिक स्वागत है। 25 अक्टूबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर सांसद संध्या राय और दिलीप सैकिया ने उनका स्वागत किया।

योगी कैबिनेट में 22 प्रस्तावों को मंजूरी, शिक्षकों-कर्मचारियों को पांच लाख तक कैशलेस इलाज

ओपन सर्च. संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पशुपालन को रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने का जरिया बनाने से लेकर शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने तक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

बैठक में पेश किए गए सभी 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें गाय पालन पर 50 फीसदी तक सब्सिडी, पशुओं के बीमा में सरकारी सहायता, नावों और स्टीमर के संचालन के लिए नियमावली, कंपनियों के विलय-विभाजन की प्रक्रिया आसान बनाने और मैनपुरी में सैनिक स्कूल के विस्तार के लिए जमीन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए थे और सभी को स्वीकृति मिल गई। सरकार ने पशुधन क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने, निवेश को प्रोत्साहित करने, जल परिवहन को व्यवस्थित करने और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा देने पर विशेष जोर दिया। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य है। इसके बावजूद कम उत्पादकता और बाजार की अव्यवस्थित व्यवस्था जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को अधिक लाभकारी बनाकर किसानों की आय बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहली बार स्टेट लाइवस्टॉक मिशन का गठन किया गया है।

सीएम की निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें, हरियाणा की उद्योग-अनुकूल नीतियों पर जताया भरोसा

गुजरात दौरे के पहले दिन हरियाणा को 12,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों की सौगात

कदम सिंह/ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा में औद्योगिक विकास को नई गति देने और प्रदेश को देश के अग्रणी निवेश गंतव्यों में स्थापित करने की दिशा में गुजरात दौरे के पहले दिन महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। इस दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ लगभग 12,000 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

यह पहल हरियाणा में निवेश की बढ़ती संभावनाओं, उद्योग जगत के विश्वास और राज्य सरकार के निवेश प्रोत्साहन प्रयासों को नई मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात के दौरे पर है। दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने विभिन्न कंपनियों के फाउंडर्स, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। इन बैठकों में कंपनियों की हरियाणा में मौजूदा गतिविधियों के विस्तार, नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और संभावित निवेश प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। एमओयू में डिफेंस टेक्सटाइल के क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये, टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में 2,000 करोड़ रुपये तथा औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित समझौते शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सौर ऊर्जा और कॉस्मेटिक निर्माण के क्षेत्र में हरियाणा में 400 करोड़ रुपये और वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति भी बनी है।

नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल गुजरात के दौरे पर है। दौरे के पहले दिन सीएम ने विभिन्न कंपनियों के फाउंडर्स, प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार हर कदम पर निवेशकों और उद्यमियों के साथ खड़ी है। प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करके युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने और निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे।

एसआईआर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ताओं को जवाब देने के लिए मिला 10 दिन का समय

नई दिल्ली.एजेंसी

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग के हलफनामे पर प्रतिवादी पक्ष को अपना जवाब देने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी है। शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब तलब किया है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई दीपावली अवकाश के बाद की जाएगी।

अदालत ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यशैली, कथित एकतरफा फैसलों और फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर दाखिल याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्यसभा सांसद डोला सेन द्वारा दायर एक नई याचिका पर भी चुनाव आयोग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया। इस मामले की सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता राकेश सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत से कहा कि चुनाव आयोग का हलफनामा सुनवाई से एक रात पहले ही मिला है, इसलिए उसका जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई दीवाली की छुट्टियों के बाद, 17 नवंबर के आसपास होने की संभावना है।

हमारे वनों की समृद्धि-मातृशक्ति के परिश्रम से तैयार उत्पाद बनें छत्तीसगढ़ की पहचान : सीएम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के दिवाली गिफ्ट पैक का किया लोकार्पण, स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बड़ा बाजार, महिला स्व-सहायता समूहों और वन उपज संग्राहकों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

ओपन सर्च. संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास में 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के दिवाली गिफ्ट पैक का लोकार्पण किया। वन धन विकास केंद्रों से जुड़ी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय एवं हर्बल उत्पादों को आकर्षक गिफ्ट पैक के रूप में तैयार किया गया है। इस पहल से जहां छत्तीसगढ़ के गुणवत्तापूर्ण स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार मिलेगा, वहीं लघु वनोपज संग्राहकों और महिला स्व-सहायता समूहों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री साय ने इस अभिनव पहल की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध वन संपदा हमारे लाखों वनवासी परिवारों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है।

हमारी सरकार का प्रयास है कि वनों से प्राप्त उपज का अधिक से अधिक मूल्य संवर्धन प्रदेश में ही हो और इसका सीधा आर्थिक लाभ वन उपज संग्राहकों तथा इससे जुड़े महिला समूहों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से हमारी माताएं-बहनें स्थानीय वनोपज को प्रसंस्कृत कर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर रही हैं। इन उत्पादों को बेहतर पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार से जोड़कर हम उनके परिश्रम को नई पहचान और आय के बेहतर अवसर दे रहे हैं। 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के दिवाली गिफ्ट पैक इसी दिशा में एक सार्थक पहल हैं। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान करते हुए कहा कि जब हम छत्तीसगढ़ में बने उत्पादों को खरीदते और उपहार में देते हैं, तो उसका लाभ सीधे हमारे वनांचल के परिवारों और महिला स्व-सहायता समूहों तक पहुंचता है। स्थानीय उत्पादों को अपनाना हमारी परंपराओं, स्थानीय उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने में हमारी सहभागिता है। उल्लेखनीय है कि 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के दिवाली गिफ्ट पैक दो श्रेणियों–प्रीमियम और सामान्य–में तैयार किए गए हैं।

'नशामुक्त बिहार' अभियान गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी

सीएम ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया

ओपन सर्च. संवाददाता

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को राज्यव्यापी 'नशामुक्त बिहार अभियान' का शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अभियान को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने और नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

यह अभियान 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक राज्यभर में चलाया जाएगा। पटना में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नशामुक्ति के लिए व्हाट्सऐप चैटबोट और हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। साथ ही, जन-जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन अगले एक महीने तक बिहार के विभिन्न जिलों में ऑडियो-विजुअल माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों और नशामुक्त जीवन के लाभों के प्रति जागरूक करेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों एवं आम नागरिकों को नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करने, दूसरों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक करने, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने और बिहार को नशामुक्त बनाने में सक्रिय योगदान देने की शपथ दिलाई।

यह अभियान 27 अक्टूबर से 26 नवंबर तक राज्यभर में चलाया जाएगा। पटना में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की

उन्होंने अभियान को जनभागीदारी से व्यापक स्तर पर चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वर्ष 2029 तक देश को नशामुक्त बनाने के लक्ष्य की दिशा में यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र शुरु

ओपन सर्च/ओ पी उनियाल

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है। इसके साथ ही राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पहली बार एक साल के भीतर दो विधानसभा सत्र आयोजित होने का नया अध्याय जुड़ गया है। इससे पहले इसी साल मार्च में भराड़ीसैंण में बजट सत्र आयोजित किया गया था। गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी। इसके बाद से यहां समय-समय पर विधानसभा की कार्यवाही संचालित होती रही है। हालांकि, कुछ वर्षों में यहां कोई सत्र आयोजित नहीं हुआ, जबकि कुछ वर्षों में एक बार विधानसभा सत्र आयोजित किया गया। वर्ष 2014 में गैरसैंण में पहली बार तीन दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित किया गया। वर्ष 2015 और 2016 में दो-दो दिन तथा वर्ष 2017 में दो दिवसीय सत्र हुआ।

हरियाणा दिवस से मध्यम आय वर्ग के परिवारों को मिलेगा चिरायु स्वास्थ्य बीमा का लाभ

ओपन सर्च ब्यूरो

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 13 अक्टूबर, 2026 की अधिसूचना के अनुसार, चिरायु विस्तार योजना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस विस्तारित योजना के तहत, पात्र परिवार मामूली वार्षिक योगदान देकर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल इलाज प्राप्त कर सकेंगे

चंडीगढ़। स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में 3 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवारों तक 'चिरायु' स्वास्थ्य योजना के लाभ का विस्तार किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग की 13 अक्टूबर, 2026 की अधिसूचना के अनुसार, चिरायु विस्तार योजना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी। इस विस्तारित योजना के तहत, पात्र परिवार मामूली वार्षिक योगदान देकर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कैशलेस अस्पताल इलाज प्राप्त कर सकेंगे। इस विस्तार से मध्यम और उच्च आय वाले अधिक से अधिक परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर होने वाले खर्च के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। योजना के अनुसार, 3 लाख रुपये से अधिक और 6 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक आय वाले परिवारों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि 6 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार 5,000 रुपये प्रति वर्ष का योगदान देंगे। पात्र परिवार पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का मुफ्त (कैशलेस) इलाज पाने के हकदार होंगे। पात्रता का सत्यापन परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के माध्यम से किया जाएगा।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि इस विस्तार से जेब से होने वाले मेडिकल खर्च को कम करने में मदद मिलेगी और अप्रत्याशित मेडिकल आपात स्थितियों का सामना कर रहे परिवारों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। मौजूदा आय श्रेणियों से परे कवरेज का विस्तार करके, सरकार का उद्देश्य हरियाणा के अधिक से अधिक निवासियों तक गुणवत्तापूर्ण अस्पताल देखभाल पहुंचाना है। यह योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के ढांचे का पालन करती है और इसमें माध्यमिक व तृतीयक (सेकेंडरी और टर्शरी) स्वास्थ्य देखभाल शामिल है। इसमें 2,694 उपचार पैकेज शामिल हैं, जिनके अंतर्गत सर्जिकल प्रक्रियाएं, चिकित्सा उपचार और डे-केयर प्रक्रियाएं आती हैं। लागू पैकेजों के तहत निर्दिष्ट दवाओं और नैदानिक सेवाओं (डायग्नोस्टिक सर्विसेज) का खर्च भी कवर किया गया है। योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें पात्र परिवार के आकार या उसके सदस्यों की आयु की कोई सीमा नहीं है। सभी पूर्व-मौजूद (पहले से चली आ रही) बीमारियां भी कवर की गई हैं। इलाज की प्रक्रियाओं में अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले तक की जाने वाली जांचें और डिस्चार्ज के बाद 15 दिनों तक होने वाले पात्र चिकित्सा खर्च भी शामिल हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि लाभार्थी राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्रावधान के तहत भारत में कहीं भी पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। लाभार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र काम करेगा। अस्पताल में भर्ती होने के समय लाभार्थियों को अपना आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड नंबर या पीपीपी आईडी प्रदान करना होगा। नामांकन प्रक्रिया को आसान और सुलभ बनाया गया है।

पात्र परिवार आधिकारिक पोर्टल https://chirayuayushman-haryana.in/ के माध्यम से अपने वार्षिक योगदान का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी डेटाबेस एकीकरण के लिए सीआरआईडी हरियाणा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ पात्र लाभार्थियों व सफल भुगतानों का विवरण साझा करेगी। लाभार्थी कार्ड सरकारी अस्पतालों, कॉमन सर्विस सेंटरों, गांव स्तर के सीएससी ऑपरेटरों और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से बनाए जाएंगे।

महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत समानता, सहयोग और सामाजिक एकता के प्रतीक : विपुल गोयल

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के आदर्श समानता, अहिंसा, सामाजिक एकता और परस्पर सहयोग की प्रेरणा देते हैं। उनकी 'एक ईंट-एक रुपया' की परंपरा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग देने और जरूरतमंदों को सशक्त बनाने का संदेश देती है। लगभग पांच हजार वर्ष पहले महाराजा अग्रसेन द्वारा दिए गए मूलमंत्र आज भी पूरी तरह प्रासंगिक हैं और भविष्य में भी समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे।

राजस्व मंत्री मंगलवार को इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, मीरपुर में महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में 'आधुनिक युग में अग्रसेन का दर्शन - सामाजिक जिम्मेदारी से लेकर स्टार्टअप और पेशेवर उत्कृष्टता तक' विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विपुल गोयल ने कहा कि अग्रवाल समाज ने सदैव सामाजिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को आगे बढ़ाने तथा सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा। उन्होंने आह्वान किया कि सभी लोग महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और सहयोग व सेवा की भावना से समाज को सशक्त बनाएं। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों से प्रेरित होकर 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अग्रोहा धाम के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

शौर्य दिवस की प्रेरणा से विद्यार्थियों ने लिया नशामुक्त समाज बनाने का संकल्प

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नशामुक्त समाज के निर्माण और युवा पीढ़ी को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सोनीपत में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शौर्य दिवस के ऐतिहासिक महत्व से प्रेरणा लेते हुए विद्यार्थियों को देशभक्ति, साहस, अनुशासन और राष्ट्र सेवा के साथ नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की प्राचार्या अरुणा कुमारी सहित 354 विद्यार्थियों और 22 शिक्षकों ने भाग लिया। हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार, आईपीएस के निर्देशन तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद एवं पुलिस उप महानिरीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस के नेतृत्व में प्रदेश भर में नशे के विरुद्ध जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ब्यूरो के जागरूकता कार्यक्रम एवं पुनर्वास प्रभारी उप निरीक्षक डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना श्रीनगर पहुंची थी और जम्मू-कश्मीर की रक्षा के लिए ऐतिहासिक अभियान शुरू किया था।

सैनिकों के अदम्य साहस, पराक्रम और बलिदान की स्मृति में मनाया जाने वाला शौर्य दिवस हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा देता है। डॉ. अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि जिस प्रकार भारतीय सैनिक देश की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अपने दायित्व निभाते हैं, उसी प्रकार युवाओं को भी नशे जैसी सामाजिक बुराई के विरुद्ध खड़े होकर समाज के उज्ज्वल भविष्य में योगदान देना चाहिए। कार्यक्रम में गीत, संगीत और काव्य के माध्यम से नशे के दुष्परिणामों को प्रभावशाली एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया। उन्होंने बताया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ-साथ उसकी शिक्षा, पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा शिक्षा, खेलकूद, योग, रचनात्मक गतिविधियों और समाजसेवा में लगाने के लिए प्रेरित किया गया। विद्यालय की प्राचार्या अरुणा कुमारी एवं शिक्षकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया कि वे नशामुक्ति का संदेश अपने परिवारों, मित्रों और आसपास के लोगों तक पहुंचाएं। गलत संगति अथवा नशीले पदार्थों के सेवन के दबाव की स्थिति में समझदारी से काम लें तथा जरूरत पड़ने पर अभिभावकों और शिक्षकों की सहायता लें।

डीएसजे संदीप सिंह ने जिला न्यायालय परिसर से पोक्सो अधिनियम जागरूकता के लिए पैदल मार्च को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना

गीता देवी/ओपन सर्च ब्यूरो

करनाल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप सिंह ने मंगलवार को जिला के सभी न्यायिक दण्डाधिकारी यो के साथ जिला न्यायालय परिसर से पोक्सो अधिनियम जागरूकता के लिए पैदल मार्च को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। पैदल मार्च में एमडीडी बाल भवन में रह रहे बच्चों ने नारा लेखन में भाग लिया व जिला न्यायालय परिसर से सेक्टर 12 तक पैदल मार्च कर जन साधारण को पोक्सो अधिनियम व बच्चों के अधिकारों बारे जागरूक किया।

इसके साथ ही सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीनाक्षी यादव की अध्यक्षता में सभी ब्लॉक से विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होने उपस्थित प्रधानाचार्य से बातचीत की और उन्हे पोक्सो अधिनियम बारे जागरूक करते हुए सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन कर, उन्हें पोक्सो अधिनियम बारे जागरूक करने और उनके अधिकारों बारे जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कृषि विभाग के सौजन्य से गांव सांतडी, खण्ड इन्द्री मे कैंपेन किसान सशक्तिकरण और चेतना अभियान के अंतर्गत किसानों के हितों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर सीजेएम मीनाक्षी यादव ने गांववासियों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं का समाधान बताया साथ ही उन्होंने गांववासियों को पराली प्रबंधन बारे जानकारी दी और सरकारी योजनाओं से अवगत किया।

नेहा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर बाल भवन में किया विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

ओपन सर्च ब्यूरो

सोनीपत। जिला बाल कल्याण परिषद, द्वारा बाल भवन में बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त एवं जिला बाल कल्याण परिषद की अध्यक्ष नेहा सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर लगभग 410 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा, कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान रंगोली, क्ले मॉडलिंग, स्केचिंग, ऑन-द-स्पॉट पोस्टर मेकिंग और फन गेम्स जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। बच्चों ने सभी गतिविधियों में पूरे उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास के साथ भाग लिया। रंगोली प्रतियोगिता में बच्चों ने रंगों के आकर्षक संयोजन से सुंदर आकृतियां बनाई, वहीं क्ले मॉडलिंग में मिट्टी से विभिन्न कलात्मक वस्तुएं तैयार कर अपनी सृजनात्मक क्षमता का परिचय दिया। स्केचिंग और पोस्टर मेकिंग में बच्चों ने अपनी कला एवं कल्पनाशीलता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। फन गेम्स ने कार्यक्रम को मनोरंजक और उत्साहपूर्ण बना दिया।

उपायुक्त नेहा सिंह ने बच्चों की प्रतिभा और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ-साथ कला, संस्कृति, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी भी अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने, आत्मविश्वास बढ़ाने तथा उनमें सकारात्मक सोच, अनुशासन और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे में कुछ विशेष करने की क्षमता होती है। बच्चों को उनकी रुचि और योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए, ताकि वे अपनी प्रतिभा को पहचानकर जीवन में बेहतर उपलब्धियां हासिल कर सकें। ऐसे आयोजन बच्चों को नई चीजें सीखने, अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और एक-दूसरे से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करते हैं। जिला बाल कल्याण अधिकारी आरती ने बताया कि जिला बाल कल्याण परिषद बच्चों के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करती रहती है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों को सकारात्मक वातावरण उपलब्ध करवाने के साथ उनकी प्रतिभा को उचित मंच प्रदान करना है।

मधुमक्खी पालकों के लिए बड़ी राहत हरियाणा सरकार ने 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' में किया शामिल

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के कृषि और बागवानी क्षेत्र से जुड़े किसानों और व्यवसायियों के हित में एक और ऐतिहासिक तथा अनूठी पहल की है। प्रदेश सरकार ने अब 'मधुमक्खी पालन' को 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' के दायरे में शामिल कर लिया है, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े पालकों को बड़ी वित्तीय सुरक्षा और राहत मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार की इस नीति से मधुमक्खी पालन का व्यवसाय करने वाले उद्यमियों और किसानों के मन से प्राकृतिक आपदाओं और अनहोनी के कारण होने वाले नुकसान की चिंता काफी हद तक कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत बाढ़ की स्थिति में मधुमक्खी के बक्से और कॉलोनियों के पानी में डूब जाने, आग लगने से उनके नष्ट होने, तथा ट्रांसपोर्टेशन (परिवहन) के दौरान दुर्घटना के कारण होने वाले नुकसान को कवर किया जाएगा, बशर्ते यह दुर्घटना हरियाणा राज्य के भीतर हुई हो और इसकी आधिकारिक एफआईआर या डीडीआर दर्ज कराई गई हो। इसके अलावा, मधुमक्खियों में किसी प्रकार की महामारी के कारण होने वाले नुकसान की स्थिति में भी मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। योजना की रूपरेखा और पात्रता स्पष्ट करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि इस बीमा का लाभ उठाने के लिए प्रति मधुमक्खी पालक अधिकतम 250 मधुमक्खी कॉलोनियां और बक्से निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही, 'भावांतर भरपाई योजना-शहद' के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा मधुमक्खी पालक को हर बॉक्स पर भावांतर भरपाई योजना यूनिट नंबर देना भी आवश्यक किया गया है।

लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक नवंबर को दिल्ली में उठेगी जनता की आवाज : कुमारी सैलजा

ओपन सर्च ब्यूरो

सिरसा। सिरसा की सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की सदस्य एवं उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का वोट ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। सांसद ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस वोट के अधिकार, चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है।

इसी क्रम में एक नवंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आयोजित रैली में हरियाणा, उत्तराखंड सहित देशभर से लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। कुमारी सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध हैं। लोकतंत्र में सत्तापक्ष के साथ विपक्ष को भी अपनी बात रखने, सरकार की नीतियों का विरोध करने और जनता से जुड़े सवाल उठाने का पूरा अधिकार है।

सांसद ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज से घबराई हुई है और राजनीतिक विरोध को दबाने के लिए विभिन्न हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस की रैली को लेकर भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया दर्शाती है कि सरकार विपक्ष के सवालों से असहज है। कुमारी सैलजा ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और कथित वोट चोरी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं।

इन आरोपों पर निष्पक्ष और पारदर्शी जवाब मिलना आवश्यक है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती चुनावी व्यवस्था पर जनता के विश्वास से जुड़ी है। कांग्रेस का संघर्ष किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए है। कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि भाजपा समाज में विभाजन पैदा करने और लोगों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की राजनीति करती रही है, लेकिन देश की जनता अब ऐसी नीतियों को समझ चुकी है।

सरकार को जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के बजाय बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर जवाब देना चाहिए। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि एक नवंबर की रैली के माध्यम से कांग्रेस चुनावी पारदर्शिता, मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और विपक्ष की लोकतांत्रिक भूमिका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी। बड़ी जनभागीदारी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जनता की जागरूकता का संदेश देगी।

वीबी जी राम जी में सवाया काम और विकास की गारंटी : डॉ. चौहान

ओपन सर्च ब्यूरो

नीलोखेड़ी। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी में बीबी जी राम जी के अंतर्गत अनुमेय कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं को धरातल पर सफल बनाने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का क्षमता निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने मनरेगा का स्थान ले चुकी विकसित भारत की रामजी योजना को ग्रामीण रोजगार और विकास का प्रभावी आधार बनाने का आवाहन किया। डॉ. चौहान ने कहा कि अनुमेय 375 विकास कार्यों की उचित योजना, पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अहम भूमिका है। प्रशिक्षण के माध्यम से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को योजनाओं की निर्धारित प्रक्रियाओं, कार्यप्रणाली तथा कार्यों के बेहतर निष्पादन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने प्रतिभागियों से आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव का उपयोग अपने कार्यक्षेत्र में करें, ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंच सके। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग से प्रोजेक्ट ऑफिसर हरिचंद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी और निर्धारित प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ होना जरूरी है।

सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद के लिए तुरंत आगे आए कृष्णलाल पंवार

ओपन सर्च ब्यूरो

चंडीगढ़। हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा खनन मंत्री कृष्णलाल पंवार ने सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता के लिए तत्काल कदम उठाकर मानवीय संवेदनशीलता और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। सड़क पर हुए हादसे को देखकर मंत्री ने अपने काफिले को तुरंत रुकवाया और घायल चालक को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से अपने काफिले में चल रही पायलट गाड़ी से अस्पताल भिजवाया। मंत्री की इस त्वरित पहल ने यह संदेश दिया कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बचाने और जरूरत के समय उसकी सहायता करने से बढ़कर कोई दूसरा कर्तव्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि मंत्री कृष्णलाल पंवार आज पानीपत जिले के मडलौडा स्थित अपने निवास से चरखी दादरी में आयोजित कबड्डी खेल ट्रायल कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान 152-डी पर जींद जिले के जुलाना के पास एक पिकअप गाड़ी और कैंटर के बीच टक्कर हो गई।

इस दुर्घटना में पिकअप गाड़ी का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक राजस्थान के पिलानी का निवासी बताया गया है। हादसे को देखते ही मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बिना किसी देरी के अपना काफिला रुकवाया और दुर्घटनास्थल पर घायल व्यक्ति की सहायता के लिए आवश्यक कदम उठाए। उन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए अपने काफिले में चल रही पायलट गाड़ी के माध्यम से घायल चालक को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की, ताकि उसे जल्द से जल्द उपचार मिल सके। इस दौरान मंत्री ने प्राथमिकता घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने को दी। मंत्री पंवार की यह पहल दर्शाती है कि जनसेवा का भाव केवल सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्रशासनिक दायित्वों तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए मौके पर आगे आना भी सामाजिक दायित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क दुर्घटना जैसी आपात स्थिति में समय पर सहायता मिलना बेहद महत्वपूर्ण होता है।

शिक्षा, नवाचार और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से देश एवं प्रदेश के विकास में अपना अहम योगदान दें युवा : असीम कुमार घोष

ओपन सर्च ब्यूरो

- आरकेएसडी कॉलेज में किया गया 35वें दीक्षांत समारोह का आयोजन
- हरियाणा के राज्यपाल घोष ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत
- लगभग 190 स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को प्रदान की गईं डिग्रियां, विद्यार्थियों को दी सफलता की शुभकामनाएं
- डिग्री के साथ ज्ञान, चरित्र और मानवीय मूल्यों को जीवन का आधार बनाएं विद्यार्थी : राज्यपाल असीम कुमार घोष

चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष ने कहा कि आज के दौर में दुनिया को केवल सवालों के जवाब जानने वाले लोगों की ही नहीं, बल्कि बेहतर सवाल पूछने और नई संभावनाओं को तलाशने का साहस रखने वाले युवाओं की भी आवश्यकता है। विद्यार्थियों की वास्तविक पहचान केवल उनकी डिग्री से नहीं, बल्कि उनकी सोच की गहराई, चरित्र की मजबूती और ज्ञान के मानवीय उपयोग से होती है।

इसलिए आप सभी डिग्री धारक शिक्षा, नवाचार, उद्यमशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता के माध्यम से देश एवं प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। साथ ही ज्ञान, चरित्र और मानवीय मूल्यों को अपने जीवन का आधार बनाएं। राज्यपाल प्रो असीम कुमार घोष मंगलवार को कैथल स्थित आरकेएसडी कॉलेज के 35वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर लगभग 190 स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने डिग्री प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा यह कार्यक्रम एक ओर विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों का उत्सव है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन की नई यात्रा की शुरुआत भी है।

आपने वर्षों तक जो ज्ञान अर्जित किया है और अब उनके सामने अपने विचारों, प्रतिभा तथा क्षमताओं से दुनिया को बेहतर बनाने का अवसर है। स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को अपने ज्ञान, अनुभव, नई सोच तथा सकारात्मक बदलाव में बदलने का प्रयास करना चाहिए। राज्यपाल प्रो. घोष ने आरकेएसडी कॉलेज की पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान में लगभग 5,000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 2,600 छात्राएं शामिल हैं।

संस्थान उनके शैक्षणिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को दिया गया ज्ञान, मार्गदर्शन और संस्कार जीवनभर उनकी अमूल्य पूंजी बने रहेंगे। शिक्षकों के विचार, व्यवहार और आदर्श विद्यार्थियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 1954 से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहा आरकेएसडी कॉलेज हरियाणा के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में अपनी पहचान रखता है। विशेष रूप से आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की सफाई, एसआईआर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के फैसलों को बताया सामूहिक

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। आयोग ने हलफनामे में कहा कि जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026 में जारी किए गए तीनों एसआईआर आदेश सर्वसम्मति से लिए गए थे। ईसीआई ने माना कि ऑनलाइन फॉर्म को देखकर ऐसा लग सकता था कि उसमें संशोधन किया गया है। 21 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन में फॉर्म 6 और घोषणा-पत्र अलग-अलग दिखाए जाएंगे, जैसा कि भौतिक फॉर्म में है।

ईसीआई ने कहा है कि मैपिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में होगी और जहां संभव होगा, ऑनलाइन कराई जाएगी। ईसीआईनेट पर चुनाव आयोग ने बताया है कि ईआरओ के आदेश के बिना किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा या हटाया नहीं जाता। नियमों के अनुपालन की जांच के लिए आईआईटी और आईआईएससी के विशेषज्ञों वाली समिति गठित की गई है। गोवा के 97 मतदाताओं के मामले पर आयोग ने अपने जवाब में कहा है कि छूट गए 97 मतदाताओं में से 88 पहले से मतदाता सूची में शामिल थे, छह विदेश में थे और तीन के पास पुर्तगाली पासपोर्ट थे। पश्चिम बंगाल की अपीलों पर चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने के खिलाफ अपीलें सीईओ, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दायर की थीं।

ईसीआई ने कहा कि ये मामले आयोग के समक्ष नहीं रखे गए थे। चुनाव आयोग ने याचिका की सुनवाई-योग्यता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को

ईसीआई ने कहा है कि मैपिंग नहीं होने वाले मतदाताओं को सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। बीएलओ उनके घर जाकर दस्तावेज जुटाएंगे। सुनवाई केवल असाधारण परिस्थितियों में होगी और जहां संभव होगा, ऑनलाइन कराई जाएगी। ईसीआईनेट पर चुनाव आयोग ने बताया है कि ईआरओ के आदेश के बिना किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में जोड़ा या हटाया नहीं जाता

हटाने जैसी है। आयोग ने मीडिया में आंतरिक दस्तावेज जारी करने से इनकार किया। ईसीआई ने कहा कि उसने किसी आंतरिक नोट या फाइल को मीडिया में जारी नहीं किया और न ही उसे जारी करने की अनुमति दी। आयोग ने ईवीएम से जुड़ी याचिकाओं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ईवीएम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट पहले ही कई बार खारिज कर चुका है। आयोग ने विस्तृत जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी और कहा कि दशहरा अवकाश के कारण आयोग ने फिलहाल संक्षिप्त जवाब दाखिल किया है और सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत, बिंदुवार जवाब देने की अनुमति मांगी है। यह हलफनामा मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कामकाज पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं के जवाब में दाखिल किया गया था।

निर्वाचन आयोग ने कहा कि उसके समक्ष दाखिल किए गए प्रति-हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी। चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर दायर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों ने एक साथ हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सीईसी पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि याचिका सिर्फ एक खबर पर आधारित है। सीईसी ज्ञानेश कुमार के एकतरफा फैसले लेने की खबर को गलत बताया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि एसआईआर के तीनों आदेश (जून 2025, अक्टूबर 2025 और मई 2026) आयोग के सर्वसम्मत फैसले हैं। हलफनामे में कहा गया है कि फाइल सिस्टम के मुताबिक फाइल पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे चुनाव आयुक्त और फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के पास जाती है। नोट या सवाल फैसले नहीं होते हैं। हलफनामे के मुताबिक, 28 जुलाई का ऑर्डर एडिशनल सेक्रेटरी ने जारी किया था। दोनों चुनाव आयुक्तों ने अगले दिन कैबिनेट सचिव को लिखा।

'जो संकटों का सामना कर आगे बढ़ता है, वही सफलता के शिखर तक पहुंचता है', पीएम मोदी ने साझा किया सुभाषित

नई दिल्ली (एजेंसी)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक सुभाषित शेयर किया है, जिसमें चुनौतियों का सामना कर सफलता के शिखर तक पहुंचने का संदेश दिया गया है। पीएम मोदी की ओर से संस्कृत श्लोक, 'न संशयमनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति। संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति॥' शेयर किया गया है, जिसका हिंदी भावार्थ है कि जो मनुष्य चुनौतियों का सामना करने का साहस नहीं रखता, उसके लिए सफलता का मार्ग कठिन बना रहता है। किंतु जो व्यक्ति साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ संकटों का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ता है, वही जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंचता है।

प्रधानमंत्री की ओर से साझा किया गया यह प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक महाभारत के शांतिपर्व के 138वें अध्याय के 34वें श्लोक से लिया गया है। बिना जोखिम उठाए बड़ी उपलब्धियां नहीं मिलती। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि मनुष्य बिना किसी खतरे या जोखिम (संशय) में पड़े कभी कल्याण या श्रेष्ठ फल नहीं देख पाता, और अगर वह संकट या जोखिम मोल लेता है और जीवित बच जाता है, तभी उसे वास्तविक सफलता या सुख देखने को मिलते हैं। यानी जीवन में बड़ी उपलब्धियां या तरक्की बिना किसी अनिश्चितता या जोखिम का सामना किए संभव नहीं हैं।

इसके माध्यम से कहा गया है कि जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन पूरी बुद्धिमत्ता और सावधानी के साथ, जिससे कि उस संकट को पार करके जीवित रह सके और फल का आनंद लिया जा सके। प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किए गए इस श्लोक के माध्यम से संदेश दिया गया है कि लोगों को चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहिए।

पत्रकार से धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर 3 नवंबर को सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह 3 नवंबर को एक गर्भवती महिला पत्रकार की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया गया है। यह मामला इंडिया ब्लॉक के नेताओं के वोटर लिस्ट के एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट परिसर तक निकाले गए मार्च के दौरान का है। मामले का जिक्र वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने किया। उन्होंने कहा कि महिला पत्रकार से जुड़ी याचिका अभी तक सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। गौरव भाटिया के जवाब में सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि मामले में पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है और इस पर 3 नवंबर को सुनवाई होगी। पत्रकार रिचा पराशर ने आरोप लगाया था कि जब वह विपक्षी नेताओं के मार्च को कवर कर रही थीं, तो राहुल गांधी ने उनका हाथ पकड़ा और आक्रामक तरीके से खींचा, जिसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें धक्का दिया और वह गिर गईं। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

तीन महीने की गर्भवती रिचा पराशर ने आरोप लगाया कि यह घटना 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विपक्षी नेताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अफरा-तफरी के बीच हुई। वहीं पार्टी नेताओं और समर्थकों ने घटना के वीडियो प्रसारित किए हैं और सवाल उठाया है कि क्या वीडियो से यह साबित होता है कि राहुल गांधी ने पत्रकार को धक्का दिया। यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत परिसर में और उसके आसपास राजनीतिक प्रदर्शनों के खिलाफ सुरक्षा उपायों की मांग वाली एक अलग याचिका की पृष्ठभूमि में आया है। 15 अक्टूबर को सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया था और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज और अन्य डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। यह मार्च इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने तब निकाला था, जब सीजेआई ने राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से एसआईआर को लेकर ज्ञापन सौंपने के लिए मिलने के अनुरोध को ठुकरा दिया था। सीजेआई ने विपक्षी नेताओं को स्थापित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आने की सलाह दी थी और कहा था कि लंबित मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाना शक्तियों के पृथक्करण के संवैधानिक सिद्धांत के विपरीत होगा।

शाहदरा थाने में वकीलों से मारपीट पर भड़के सौरभ भारद्वाज, बोले-पुलिस की बर्बरता और सरकार के खिलाफ एकजुट हों अधिवक्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)

शाहदरा पुलिस स्टेशन में वकीलों के साथ मारपीट का मामला सामने आने के बाद अधिवक्ताओं की हड़ताल और पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद गहरा गया है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस मामले में अधिवक्ताओं से एकजुट होने की अपील करते हुए पुलिस की कार्यशैली और सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि पुलिस की बर्बरता और सरकार के अहंकार के खिलाफ सभी अधिवक्ताओं को एक साथ खड़ा होना चाहिए। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक, शाहदरा थाने में वकीलों के साथ कथित मारपीट की घटना के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। वकीलों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने के बदले रिश्वत ली थी। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि वकीलों की शिकायत पर थाना प्रभारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बजाय पुलिस ने अधिवक्ताओं के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी। उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कानून के रखवाले ही न्याय की मांग कर रहे हों और उनके खिलाफ ही कार्रवाई होने लगे, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। सौरभ भारद्वाज ने अपने बयान में पत्रकार से जुड़े एक पुराने मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब एक पत्रकार ने एसीपी विवेक भगत के खिलाफ कथित छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, तब बाद में पुलिस ने पत्रकार के खिलाफ ही जातिसूचक टिप्पणी करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया था।

एक नवंबर को कांग्रेस की रैली : 14 जोन में बंटा रामलीला मैदान : 3500 पुलिसकर्मी संभालेंगे मोर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)

मध्य दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को होने वाली कांग्रेस की रैली के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पूरे मैदान को 14 जोन में बांटकर सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रैली में 30 से 35 हजार लोगों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए मैदान और आसपास के इलाकों में 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा निगरानी के लिए कई कंट्रोल रूम भी तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने सोमवार को रामलीला मैदान में सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल रेंज के संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा के अनुसार, मैदान के 14 जोन में से प्रत्येक की जिम्मेदारी सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी। दो जोन की निगरानी एडिशनल डीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा रिजर्व फोर्स की 10 कंपनियां भी बुलाई गई हैं।

बॉडी वोर्न कैमरों से लैस होंगे पुलिसकर्मी

रैली के दौरान पूरे मैदान पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को बॉडी वोर्न कैमरे दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रखर वैन, पीसीआर वैन और सीसीटीवी कैमरों से लैस वाहनों को भी तैनात किया जाएगा। मैदान के प्रवेश और निकास मार्गों के साथ आसपास के क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी। निगरानी के लिए सीसीटीवी और कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम समेत कई केंद्र बनाए जा रहे हैं। पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक, रैली आयोजकों ने शुरुआती अनुमान में 30 से 35 हजार लोगों के शामिल होने की संभावना जताई है। वास्तविक संख्या का आकलन करने के लिए पुलिस का खुफिया विभाग भी सक्रिय है। रैली रविवार को होगी, लेकिन त्योहारी मौसम में खरीदारी के लिए लोगों की आवाजाही बढ़ने से यातायात प्रभावित होने की आशंका है।

दिल्ली : एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर फिर मिले पोस्टर, दीवारों पर भी लिखावट, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

नई दिल्ली (एजेंसी)

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पोस्टर चिपकाने और दीवारों पर काली स्याही से लिखावट करने का एक और मामला सामने आया है। शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर 24 अक्टूबर को इमरजेंसी गेट नंबर 5 के पास दीवार पर पोस्टर चिपके मिले, जबकि गेट नंबर 7 के पास शाफ्ट की दीवार पर काली स्याही से कुछ लिखा हुआ मिला। मामले में आईजीआई एयरपोर्ट मेट्रो पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और मेट्रो रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब कुछ दिन पहले इसी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर चलने वाली मेट्रो ट्रेन के अंदर भी दो पोस्टर मिले थे। 20 अक्टूबर को नई दिल्ली से यशोभूमि स्टेशन पहुंची ट्रेन की जांच के दौरान ऑपरेटर ने एक सीट पर पोस्टर देखे थे। पुलिस शिकायत के मुताबिक, ट्रेन के स्टेशन पहुंचने के बाद निरीक्षण के दौरान इन पर नजर पड़ी। ए4 आकार के काले-सफेद कागजों पर छपे इन पोस्टरों में पिछले कुछ वर्षों में देश में हुए बदलावों और केंद्र सरकार के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए गए थे। पोस्टरों में दिए गए क्यूआर कोड के जरिए लोगों को एक ऑनलाइन समूह से जुड़ने का भी न्योता दिया गया था। ट्रेन में मिले पोस्टरों को हटाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले की जांच में स्पेशल सेल को भी शामिल किया गया था। अब शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पर पोस्टर चिपकाने और दीवारों पर लिखावट का नया मामला सामने आने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं।

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई ने भेजा याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी को समन, पूछताछ के लिए बुलाया

नई दिल्ली (एजेंसी)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी को समन जारी किया है। एजेंसी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने आशुतोष नेगी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के अनुसार, सीबीआई ने पेशे से पत्रकार और याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी को मंगलवार को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है।

नेगी को इस हाईप्रोफाइल हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मार्च 2024 में, उत्तराखंड पुलिस ने इस मामले पर रिपोर्टिंग करने के लिए नेगी को गिरफ्तार भी किया था। हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इस महीने की शुरुआत में एक महिला अधिकारी समेत सीबीआई की चार सदस्यीय टीम ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी। सोमवार को, उत्तराखंड पुलिस ने एक पूर्व भाजपा विधायक के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ी एक अलग एफआईआर के सिलसिले में सनावर को सहारनपुर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी भंडारी हत्याकांड के सिलसिले में सीबीआई अदालत के सामने पेश किए जाने से एक दिन पहले हुई थी। इससे पहले, सनावर ने दिल्ली में अंकिता भंडारी के माता-पिता के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। एक वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने यह मांग भी की थी कि सीबीआई को मीडिया की मौजूदगी में उनसे पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि यह जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज की निगरानी में नहीं हो रही है।

बता दें कि 2022 में 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट भंडारी की हत्या ने पूरे उत्तराखंड में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। वह एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर दी गई। उसके शव को नहर में फेंक दिया गया था, जो लगभग एक सप्ताह बाद बरामद हुआ। एक विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मामले की विस्तृत जांच के बाद अदालत में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

इसमें 97 गवाहों के नाम शामिल थे, जिनमें से 47 ने अदालत के सामने गवाही दी। मुख्य आरोपी और रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य के साथ आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आर्य को हत्या, सबूतों के साथ छेड़छाड़, उत्पीड़न और अनैतिक तस्करी सहित कई गंभीर आरोपों में दोषी पाया गया। हालांकि, परिजनों की बार-बार मांग के बाद इस साल फरवरी में सीबीआई ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच अपने हाथ में ली थी।

दिल्ली : 59 निगरानी केंद्र, फिर भी दिल्ली के हर इलाके की हवा की सही तस्वीर नहीं, बदलता है प्रदूषण का स्तर

नई दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली में वायु प्रदूषण मापने के लिए देश का सबसे बड़ा निगरानी नेटवर्क है। शहर में 59 केंद्रों से मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है। इसके बावजूद इन आंकड़ों से हर इलाके की हवा की वास्तविक स्थिति का सटीक पता नहीं चलता। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसकी प्रमुख वजह निगरानी केंद्रों की लोकेशन और उनके आसपास की भौगोलिक परिस्थितियां हैं।

हरित क्षेत्र, व्यस्त सड़कें, औद्योगिक इकाइयां, निर्माण स्थल और घनी आबादी प्रदूषण के स्तर को अलग-अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। दिल्ली के कई निगरानी केंद्र हरित क्षेत्रों के आसपास स्थित हैं। मंदिर मार्ग, अरविंदो मार्ग, लोधी रोड, सीरी फोर्ट और पूसा इसके उदाहरण हैं। दूसरी ओर, वजीरपुर, बवाना, जहांगीरपुरी, नरेला, ओखला, पटपड़गंज और झिलमिल जैसे इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां प्रदूषण को प्रभावित करती हैं। चांदनी चौक जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में भीड़ और यातायात की स्थिति अलग है, जबकि आनंद विहार और आईटीओ में वाहनों से निकलने वाले धुएं का असर अधिक हो सकता है। आईआईटी दिल्ली के 2023 के एक अन्य अध्ययन में आबादी, भूमि उपयोग और प्रदूषण उत्सर्जन जैसे कारकों के आधार पर पीएम2.5 निगरानी केंद्रों की स्थिति का आकलन किया गया। अध्ययन में सामने आया कि निगरानी नेटवर्क के सभी केंद्रों की क्षेत्रीय पहुंच और अलग-अलग इलाकों की हवा का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता समान नहीं है। आईआईटी दिल्ली के सिविल एवं पर्यावरण इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर मुकेश खरे के मुताबिक, घनी शहरी बसावट में एक स्टेशन करीब दो से तीन किलोमीटर के क्षेत्र की हवा की स्थिति समझने में मदद कर सकता है।

दिल्ली पुलिस ने कालिंदी गुंज इलाके से दो कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली पुलिस ने दक्षिण-पूर्व जिले के कालिंदी कुंज इलाके में दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक अपराधी कुख्यात 'माया गैंग' का सदस्य है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चाकू बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क पर होने वाले अपराधों को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग, बीट पेट्रोलिंग और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग की जाती है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिसकर्मी इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात करीब 9 बजे उन्होंने दो लोगों को संदिग्ध तरीके से मोटरसाइकिल पर जाते देखा। जब पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो वे रुकने के बजाय भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल गई, जिससे दोनों सवार सड़क पर गिर पड़े। सतर्क पुलिसकर्मियों ने तुरंत दोनों को मौके पर ही काबू कर लिया और पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान सुमित बेनीवाल और उमर अंसारी के रूप में हुई।

तलाशी लेने पर आरोपी सुमित बेनीवाल के पास से बटन से खुलने वाला एक अवैध चाकू बरामद हुआ। आरोपी उमर अंसारी से चोरी का एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी सुमित बेनीवाल से बरामद एक अन्य मोबाइल फोन और आरोपियों की ओर से इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया। इसके बाद दोनों के खिलाफ कालिंदी कुंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी अमर कॉलोनी थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर हैं। आरोपी उमर अंसारी 'माया गैंग' का सदस्य है और फिलहाल वह मकोका के एक मामले में भी वांछित है। अधिकारियों ने बताया कि अपराधी उमर पहले भी 11 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें चोरी, झपटमारी और सेंधमारी जैसे मामले शामिल हैं। वहीं, सुमित बेनीवाल एक कुख्यात चोर और झपटमार है। वह गंभीर अपराधों के 18 मामलों में शामिल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद 11 मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें एक मकोका का मामला भी शामिल हैं।

जयशंकर ने लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलोइस से मुलाकात की, भारत-ईएफटीए समझौते से मिलने वाले अवसरों पर हुई चर्चा

नई दिल्ली (एजेंसी)

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'लिकटेंस्टीन के युवराज एलोइस के भारत दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करके खुशी हुई। भारत और लिकटेंस्टीन के बीच साझेदारी कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें भारत-ईएफटीए टीईपीए से मिलने वाले अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को लिकटेंस्टीन के युवराज एलोइस से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों के साथ-साथ भारत-ईएफटीए व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) के तहत उभर रहे नए अवसरों पर चर्चा की।

जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'लिकटेंस्टीन के युवराज एलोइस के भारत दौरे के दौरान उनसे मुलाकात करके खुशी हुई। भारत और लिकटेंस्टीन के बीच साझेदारी कई क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें भारत-ईएफटीए टीईपीए से मिलने वाले अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।' उन्होंने आगे लिखा, आज बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी होने वाली बैठक का भी इंतजार है, जिससे दोनों देशों के सहयोग को और आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे पहले मंगलवार को प्रिंस एलोइस का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रिंस एलोइस ने कहा कि भारत की राजकीय यात्रा पर आना उनके लिए सम्मान की बात है।

उन्होंने यह भी कहा कि लिकटेंस्टीन भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अद्भुत देश की पहली राजकीय यात्रा के अवसर पर भारत आकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। यह ऐतिहासिक यात्रा इस बात का प्रमाण है कि लिकटेंस्टीन भारत के साथ अपने रिश्तों को कितना महत्व देता है।

भारत के साथ हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) का जिक्र करते हुए प्रिंस एलोइस ने इसे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि हम इस गति को आगे बढ़ाने और भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों और कई अन्य क्षेत्रों में हमारे देशों की क्षमताएं एक-दूसरे की पूरक हैं।

सम्पादकीय

यमुना की लहरों पर पर्यटन की नई उम्मीद

यमुना नदी में रिवर क्रूज का ट्रायल राजधानी दिल्ली में पर्यटन की नई संभावनाओं को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल है। यह प्रयास न केवल नदी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है, बल्कि यमुना के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यदि यह परियोजना सफल होती है, तो दिल्ली में पर्यटन के नए आकर्षण विकसित होने के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों को भी गति मिल सकती है।

दिल्ली ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक विकास के लिए देश-विदेश में प्रसिद्ध है। लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट और अनेक ऐतिहासिक स्थल हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ऐसे में यमुना नदी पर रिवर क्रूज की शुरुआत राजधानी के पर्यटन अनुभव को एक नया आयाम दे सकती है। नदी के किनारे बसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं। इससे पर्यटकों को दिल्ली को एक अलग नजरिए से देखने का अवसर मिलेगा।

सरकार और संबंधित एजेंसियों को चाहिए कि क्रूज के संचालन से पहले सुरक्षा मानकों, जल की गुणवत्ता, नौवहन व्यवस्था और आपातकालीन सुविधाओं का समुचित आकलन करें। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्रूज से निकलने वाला कचरा, ईंधन या अन्य प्रदूषक नदी के पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। जहां संभव हो, पर्यावरण के अनुकूल तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा आधारित प्रणालियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, जीवनरक्षक उपकरण और स्पष्ट आपातकालीन प्रोटोकॉल भी अनिवार्य होने चाहिए।

इस परियोजना का एक सकारात्मक पहलू रोजगार सृजन भी हो सकता है। क्रूज संचालन, पर्यटन सेवाओं, स्थानीय परिवहन, खानपान और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। यदि स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण देकर इस व्यवस्था से जोड़ा जाए, तो पर्यटन का लाभ व्यापक स्तर पर समाज तक पहुंच सकता है। साथ ही, दिल्ली की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रमों और नदी से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों को पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करके इस अनुभव को अधिक सार्थक बनाया जा सकता है।

खेती की लागत बढ़ी, लेकिन किसानों की कमाई नहीं

गायत्री

खेती किसानी एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया है, जिसमें किसान को हर मौसम में पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन उस पैसे के वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। यही कारण है कि आर्थिक रूप से कमजोर, छोटे और सीमांत स्तर के किसानों के लिए यह हमेशा एक जोखिम वाला काम रहता है। राजस्थान के लूणकरणसर जैसे इलाकों में खेती करने वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए तो यह अनिश्चितता और भी बड़ी चुनौती है। उन्हें बुवाई के समय अच्छे बीज मिलेंगे या नहीं, सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी होगा या नहीं, बारिश फसल की जरूरत के मुताबिक होगी या नहीं और मंडी में उपज का उचित भाव मिलेगा या नहीं, इन सवालों के बीच उन्हें खेती की तैयारी करनी पड़ती है।

खेती की पहली चुनौती अक्सर बुवाई से पहले ही शुरू हो जाती है। किसान को सही समय पर बीज चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुकूल बुवाई का समय निकल जाने पर अच्छी फसल की संभावना भी प्रभावित हो सकती है। बड़ी जोत वाले किसान किसी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पैसा जुटा सकते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास विकल्प सीमित होते हैं। बीज, खाद और खेत तैयार करने में पहले ही खर्च हो चुका होता है। ऐसे में बुवाई में देरी का मतलब केवल कुछ दिन गंवाना नहीं, बल्कि पहले से किए गए निवेश के जोखिम को बढ़ाना भी है। इसके बाद सिंचाई का सवाल सामने आता है। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पानी खेती की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में से एक है। जिन किसानों के पास सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वे मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर रहते हैं। यदि बारिश सही समय पर और जरूरत के मुताबिक हो जाए, तो फसल अच्छी होने की उम्मीद बढ़ती है। लेकिन मानसून में देरी हो जाए, बीच में लंबा सूखा पड़ जाए या एक साथ बहुत अधिक बारिश हो जाए, तो फसल को नुकसान पहुंच सकता है।

किसान की आर्थिक परेशानी का एक बड़ा कारण यह है कि खेती में होने वाले खर्च और उससे मिलने वाली आमदनी के बीच संतुलन नहीं बन पाता। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के वर्ष 2019 के स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार, जुलाई 2018 से जून 2019 के दौरान भारत के एक कृषि परिवार की औसत मासिक आय 10,218 रुपये थी। इसमें मजदूरी से 4,063 रुपये, फसल उत्पादन से खर्च घटाने के बाद 3,798 रुपये, पशुपालन से 1,582 रुपये और गैर-कृषि व्यवसाय से 641 रुपये की औसत मासिक आय शामिल थी।

राजस्थान में इसी सर्वेक्षण के अनुसार कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 12,520 रुपये आंकी गई थी। यह आंकड़ा केवल फसल बेचने से होने वाली कमाई नहीं, बल्कि मजदूरी और दूसरे स्रोतों से प्राप्त आय को भी जोड़ता है। इसलिए इसे खेती से होने वाला शुद्ध लाभ समझना सही नहीं होगा। ये आंकड़े वर्ष 2018-19 के हैं, वर्तमान आय का अनुमान नहीं, लेकिन वे यह जरूर दिखाते हैं कि किसान परिवारों की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए उनकी पूरी आमदनी और खर्च का हिसाब देखना जरूरी है।

जब बारिश की अनिश्चितता के कारण फसल खराब हो जाती है, तो किसान के सामने अगली फसल की तैयारी का सवाल खड़ा हो जाता है। बीज, खाद, डीजल और मजदूरी के लिए फिर से पैसा चाहिए। जिन परिवारों के पास बचत नहीं होती, वे साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हो सकते हैं। कर्ज मिलने से तत्काल जरूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन ब्याज की जिम्मेदारी अगली फसल के साथ जुड़ जाती है। यदि अगली फसल भी अच्छी नहीं हुई या मंडी में उचित कीमत नहीं मिली, तो पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेने की नौबत आ सकती है।

एनएसओ के इसी सर्वेक्षण के मुताबिक, देश के 50.2 प्रतिशत कृषि परिवार कर्जदार थे और प्रति कर्जदार कृषि परिवार का औसत बकाया कर्ज 74,121 रुपये था। यह आंकड़ा किसानों के कर्ज में डूबे होने की भयावह सच्चाई को दर्शाता है। फसल तैयार होने के बाद भी किसान की चिंता खत्म नहीं होती। उसे मंडी में अपनी उपज का ऐसा भाव चाहिए, जिससे बीज, खाद, सिंचाई, मजदूरी, परिवहन और दूसरे खर्च निकालने के बाद परिवार की जरूरतों के लिए कुछ पैसा बच सके। यदि बाजार में कीमत कम मिलती है, तो अच्छी फसल होने के बावजूद किसान को अपेक्षित आमदनी नहीं मिलती। ऐसे में न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि पात्र किसानों की उपज की खरीद प्रभावी ढंग से हो और उन्हें खरीद केंद्रों तक पहुंचने में परेशानी न हो।

खेती की आर्थिक व्यवस्था पर चर्चा करते समय महिलाओं के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ग्रामीण परिवारों में महिलाएं बुवाई, निराई, कटाई, पशुओं की देखभाल, चारा जुटाने और घरेलू जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कई बार खेत में उनके काम के घंटे लंबे होते हैं, लेकिन आर्थिक फैसलों, प्रशिक्षण, ऋण और सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच सीमित रहती है।

जंतर-मंतर पर प्रतिबंध, फिर भी सड़कों पर आंदोलन

सौरभ वार्ष्णेय

वोट चोरी के आरोपों से शुरू हुआ आंदोलन, सरकार की जवाबदेही, विपक्ष की भूमिका और युवाओं की बेचैनी के बीच लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े कर रहा है। देश में चुनावी पारदर्शिता और कथित 'वोट चोरी को लेकर शुरू हुआ आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो अक्टूबर से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक माहौल लगातार गर्म बना हुआ है। जंतर-मंतर जैसे निर्धारित स्थानों पर प्रदर्शन से संबंधित प्रतिबंधों और प्रशासनिक सीमाओं के बीच आंदोलन की आवाज सड़कों तक सुनाई दे रही है। विपक्षी दलों के साथ युवाओं की भागीदारी और स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने वाले यूट्यूबरों तथा डिजिटल पत्रकारों की सक्रियता ने इस मुद्दे को एक नया आयाम दिया है। सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन को केवल राजनीतिक विरोध के रूप में देखा जाना चाहिए, या फिर इसके पीछे लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता के विश्वास से जुड़ी चिंताओं को भी समझने की आवश्यकता है?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां चुनाव केवल सरकार बनाने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की इच्छा व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर हैं। मतदाता अपने मत के जरिए सत्ता को स्वीकार करता है और आवश्यकता पडने पर उसे बदलने का अधिकार भी रखता है। इसलिए चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर उठने वाले सवालों को गंभीरता से सुनना लोकतांत्रिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। हालांकि, वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों को प्रमाणों और तथ्यों के आधार पर परखा जाना भी उतना ही आवश्यक है। आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना दो अलग-अलग बातें हैं। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि न तो सवाल पूछने वालों को बिना सुने खारिज किया जाए और न ही बिना प्रमाण किसी आरोप को अंतिम सत्य मान लिया जाए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के सामने विरोध प्रदर्शनों से निपटने की चुनौती रहती है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है, लेकिन इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते समय नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान भी जरूरी है। यदि किसी स्थान पर सुरक्षा, यातायात या कानून-व्यवस्था से संबंधित प्रतिबंध लगाए जाते हैं, तो उनके पीछे स्पष्ट कारण होने चाहिए और उनका पालन निष्पक्ष तरीके से कराया

जाना चाहिए। सरकार की आलोचना करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्था विरोधी मान लेना उचित नहीं है। उसी प्रकार आंदोलन के नाम पर कानून तोडने या आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता।

लोकतंत्र में सरकार और प्रदर्शनकारियों, दोनों से जिम्मेदार आचरण की अपेक्षा की जाती है। यदि आंदोलन को लेकर यह धारणा बनती है कि सरकार असहमति की आवाज को जनता तक पहुंचने से रोकना चाहती है, तो इससे राजनीतिक अविश्वास बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि आंदोलनकारी तथ्यों के बजाय केवल भावनाओं के आधार पर दावे करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता भी प्रभावित होती है। बेहतर रास्ता यही है कि चुनावी शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो, संबंधित संस्थाएं तथ्यों के साथ जवाब दें और जनता के सामने स्थिति स्पष्ट की जाए। विपक्ष का काम केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना और जनता के सामने वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना भी है।

यदि विपक्ष चुनावी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाता है, तो उसे ठोस साक्ष्य, व्यवस्थित शिकायतें और तथ्यात्मक तर्क सामने रखने चाहिए। केवल नारों और राजनीतिक आरोपों से जनता का विश्वास लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता। साथ ही, सरकार को भी यह समझना होगा कि विपक्ष की हर आलोचना को राजनीतिक षड्यंत्र बताकर खारिज कर देना समस्या का समाधान नहीं है। लोकतंत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष एक-दूसरे के प्रतिद्वंद्वी अवश्य हैं, लेकिन दोनों की जवाबदेही अंततः जनता के प्रति है। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता भी इसी में है कि उसके निर्णयों, प्रक्रियाओं और शिकायत निवारण व्यवस्था पर जनता का भरोसा बना रहे।

इस आंदोलन के बीच यूट्यूबरों और स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारों की भूमिका विशेष रूप से ध्यान खींचती है। पहले समाचारों और राजनीतिक विमर्श पर मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव था, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया ने आम नागरिकों को भी अपनी बात व्यापक स्तर पर रखने का अवसर दिया है। आज कोई युवा घटनास्थल से वीडियो साझा कर सकता है, किसी सरकारी दावे की पड़ताल कर सकता है और उन मुद्दों को सामने ला सकता है जिन्हें पर्याप्त जगह नहीं मिल रही हो। यह बदलाव लोकतंत्र के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। स्वतंत्र डिजिटल पत्रकारिता सत्ता से सवाल पूछने और जनता की समस्याओं को सामने लाने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन हर यूट्यूबर स्वतः पत्रकार नहीं बन जाता। विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए तथ्यों की पुष्टि, दोनों पक्षों को सुनना, स्रोतों की जांच करना और गलत सूचना फैलाने से बचना अनिवार्य है। वायरल होना और विश्वसनीय होना अलग-अलग बातें हैं।

इसलिए डिजिटल माध्यमों से उठने वाली आवाजों को केवल उनकी राजनीतिक पसंद के आधार पर खारिज करना उचित नहीं है। उनकी सामग्री की जांच तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। स्वतंत्र पत्रकारिता का वास्तविक महत्व तभी है, जब वह सत्ता से भी सवाल पूछे और विपक्ष के दावों की भी निष्पक्ष पड़ताल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं के सामने विकास, रोजगार, अवसरों और बेहतर भविष्य की उम्मीदें रखी थीं। आज युवाओं का एक वर्ग रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, महंगाई, शिक्षा और राजनीतिक जवाबदेही जैसे सवालों को लेकर मुखर दिखाई देता है। ऐसे में किसी भी आंदोलन में युवाओं की भागीदारी को केवल राजनीतिक दलों के प्रभाव का परिणाम मान लेना अधूरा विश्लेषण होगा।

युवाओं की अपेक्षाएं बदल रही हैं। वे केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि उनके परिणाम भी देखना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि रोजगार के अवसर कितने बढ़े, शिक्षा कितनी सुलभ हुई, सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता कितनी मजबूत हुई और उनकी समस्याओं पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई की गई। यह जरूरी नहीं कि आंदोलन में शामिल प्रत्येक युवा किसी एक राजनीतिक विचारधारा का समर्थक हो।

डिजिटल भारत : बदलती तस्वीर और चुनौतियां

रमेश धवाला

भारत में पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल तकनीक ने हमारे दैनिक जीवन को काफी बदल दिया है। कभी बिजली का बिल जमा करने, पैसे भेजने या सरकारी प्रमाणपत्र बनवाने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। आज इनमें से अनेक काम मोबाइल फोन से किए जा सकते हैं। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान ने देश में डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हालांकि इस बदलाव के साथ एक सवाल भी जुड़ा है कि क्या इन सुविधाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है? डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा उद्देश्य सरकारी सेवाओं को आम नागरिक के लिए सरल और सुलभ बनाना रहा है। आज अनेक प्रमाणपत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डिजिलॉकर जैसी सुविधाओं ने जरूरी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पडने पर उपलब्ध कराने का रास्ता आसान किया है। इससे लोगों के समय और पैसे की बचत हुई है। लेकिन कई बार वेबसाइट ठीक से काम नहीं करती या आवेदन लंबे समय तक लंबित रहते हैं। ऐसी स्थिति में नागरिक को वही परेशानी उठानी पड़ती है जिससे बचाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई गई थी। इसलिए तकनीक के विस्तार के साथ प्रशासनिक जवाबदेही भी जरूरी है। डिजिटल भुगतान ने भी भारतीय समाज में बड़ा बदलाव लाया है। आज छोटे दुकानदार, सब्जी विक्रेता और रेहड़ी लगाने वाले भी यूपीआई से भुगतान स्वीकार कर रहे हैं। इससे नकद पैसे रखने की जरूरत कम हुई है और लेन-देन अधिक सुविधाजनक बना है। हालांकि इसके साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं ने नई चिंताएं पैदा की हैं। फर्जी संदेश, अनजान लिंक और ओटीपी के माध्यम से ठगी के मामले बताते हैं कि डिजिटल सुविधाओं के साथ लोगों को साइबर सुरक्षा की जानकारी देना भी आवश्यक है।

सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंचाने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से बिचौलियों की भूमिका कम करने में सहायता मिली है। फिर भी कुछ लोगों को आधार, बैंक खाते या तकनीकी समस्याओं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बुजुर्गों और कम पढ़े-लिखे नागरिकों के लिए ये प्रक्रियाएं आसान नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सहायता केंद्रों और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ जाती है। किसी पात्र व्यक्ति को केवल तकनीकी समस्या के कारण सरकारी सहायता से वंचित नहीं होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी डिजिटल तकनीक की उपयोगिता बढ़ी है। ऑनलाइन कक्षाओं, अध्ययन सामग्री और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने विद्यार्थियों के लिए नए अवसर पैदा किए हैं।

इसी प्रकार स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और डिजिटल रिकॉर्ड से मरीजों को सुविधा मिल सकती है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का उद्देश्य पात्र परिवारों को उपचार के खर्च से राहत देना है। लेकिन यह भी समझना होगा कि डिजिटल कार्ड, ऑनलाइन पाठ्यक्रम या प्रमाणपत्र अपने आप बेहतर शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी नहीं हैं। इनके लिए अच्छे संस्थान, प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक संसाधन भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में डिजिटल सुविधाओं का महत्व और अधिक है। यहां अनेक गांव जिला मुख्यालयों और सरकारी कार्यालयों से काफी दूर स्थित हैं।

किसी छोटे से काम के लिए भी लोगों को लंबी यात्रा करनी पड़ती है। हिमसेवा और लोकमित्र केंद्रों जैसी व्यवस्थाएं इस दूरी को कम करने में सहायक हो सकती हैं। यदि गांव में ही प्रमाणपत्र, बिल भुगतान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों, तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रदेश के पर्यटन और बागवानी क्षेत्रों में भी डिजिटल तकनीक नई संभावनाएं लेकर आई है।

छोटे होटल और होमस्टे संचालक ऑनलाइन बुकिंग से पर्यटकों तक पहुंच रहे हैं। बागवान मौसम, मंडी भाव और बाजार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे उनके लिए बेहतर निर्णय लेना संभव होता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में कमजोर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या अब भी गंभीर है। कई दूरदराज के गांवों में इंटरनेट की गति इतनी कम होती है कि सामान्य ऑनलाइन आवेदन भरना भी मुश्किल हो जाता है। डिजिटल भारत की एक बड़ी चुनौती समाज में मौजूद डिजिटल असमानता है।

शहरों में रहने वाले शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्षम लोगों के लिए तकनीक का उपयोग अपेक्षाकृत आसान है। इसके विपरीत गरीब परिवारों, बुजुर्गों और ग्रामीण नागरिकों के सामने अनेक कठिनाइयां हैं। स्मार्टफोन की कीमत, इंटरनेट का खर्च, भाषा की समस्या और तकनीकी जानकारी का अभाव उन्हें पीछे छोड़ सकता है। इसलिए डिजिटल सेवाओं को केवल अंग्रेजी या कठिन प्रशासनिक भाषा तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हिंदी और स्थानीय भाषाओं में सरल निर्देश उपलब्ध कराना भी जरूरी है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा का है। आज बैंक, पहचान और स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत-सी जानकारी डिजिटल माध्यमों में दर्ज होती है।

इसका गलत उपयोग लोगों के लिए गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए सरकार और संबंधित संस्थाओं को डेटा सुरक्षा, शिकायत निवारण और साइबर जागरूकता पर लगातार ध्यान देना होगा। लोगों का विश्वास बनाए रखना किसी भी डिजिटल व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है। निस्संदेह डिजिटल इंडिया ने देश में सुविधाओं के नए रास्ते खोले हैं।

लेकिन इसकी सफलता का आकलन केवल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं, मोबाइल ऐप या ऑनलाइन लेन-देन की बढ़ती संख्या से नहीं किया जा सकता। असली सफलता तब होगी जब किसी दूरस्थ गांव का बुजुर्ग बिना परेशानी अपनी पेंशन प्राप्त कर सके, कोई विद्यार्थी संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे और सामान्य नागरिक को छोटे से छोटे काम के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय न जाना पड़े। तकनीक तभी सार्थक है जब वह लोगों का जीवन आसान बनाए।

वेज या नॉनवेज : भोजन की थाली पर सियासत क्यों?

विनोद पाठक

भारत में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, अपितु हमारी परंपराओं और क्षेत्रीय पहचान का भी हिस्सा है। कहीं शाकाहार जीवनशैली और आस्था से जुड़ा है तो कहीं मछली-मांस रोजमर्रा के खान-पान और पारिवारिक परंपरा का हिस्सा है। देश में भोजन की इतनी विविधता है कि किसी एक तरीके को पूरे भारत की पहचान नहीं बनाया जा सकता। इसके बावजूद खान-पान को लेकर बार-बार राजनीतिक विवाद खड़े होते हैं। कभी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का मेन्यू मुद्दा बन जाता है, कभी धार्मिक उपदेश पर टकराव शुरू हो जाता है और कभी किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की निजी पसंद पर सवाल उठने लगते हैं। आखिर भोजन की थाली को सियासत का अखाड़ा बनाने की जरूरत क्यों है? हाल के दिनों में तीन घटनाओं ने इस सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है।

सितंबर 2026 में नई दिल्ली में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं के लिए आयोजित रात्रिभोज में केवल शाकाहारी व्यंजन परोसे गए। इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मेन्यू को लेकर सवाल उठाए।

पश्चिम बंगाल में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की दुर्गा पूजा के दौरान मछली-मांस न खाने की अपील पर विवाद हुआ। अब केरलम के नए राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर के लोकभवन की रसोई में शाकाहारी भोजन बनाए जाने के निर्देश पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। तीनों घटनाओं का संदर्भ अलग है, लेकिन इनसे जुड़ा बड़ा सवाल एक ही है, खान-पान की पसंद को राजनीतिक संघर्ष में क्यों बदला जाए?

सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए रात्रिभोज आयोजित किया। इसमें कंडवी, मशरूम गलौटी, पनीर लबाबदार, हिमालयी गुच्छी से बने व्यंजन, बाजरे का पुलाव और पारंपरिक मिठाइयों सहित कई शाकाहारी पकवान परोसे गए। मेन्यू पूरी तरह शाकाहारी था। अगले दिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत के 80 प्रतिशत लोग मांसाहारी हैं और भारतीय मांसाहारी भोजन स्वादिष्ट है। उन्होंने छोले-भटूरे की तस्वीर भी साझा की। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने इस टिप्पणी को ब्रिक्स रात्रिभोज के मेन्यू से जोड़ते हुए सरकार की आलोचना की।

भारत में व्यंजनों की विविधता

इस विवाद में दो बातें अलग-अलग समझने की जरूरत है। पहली, भारत की खान-पान संस्कृति शाकाहारी और मांसाहारी, दोनों तरह के व्यंजनों से समृद्ध है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर इस विविधता को सामने रखने के लिए विभिन्न विकल्प उपलब्ध कराना अच्छी मेजबानी का हिस्सा हो सकता है। दूसरी, किसी आयोजन में केवल शाकाहारी भोजन परोसे जाने को अपने आप में किसी विचारधारा को थोपने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा था। ऐसे आयोजन में मेन्यू तय करना मेजबान की व्यवस्थाओं का हिस्सा है। भारत अपने क्षेत्रीय व्यंजनों, पारंपरिक पकवानों और मोटे अनाज से बने भोजन को दुनिया के सामने रख सकता है। शाकाहारी भारतीय भोजन भी हमारी पाक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसे विदेशी मेहमानों के सामने प्रस्तुत करने में कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। हां, मेहमानों की खान-पान संबंधी जरूरतों और पसंद का ध्यान रखना भी अच्छी मेजबानी का तकाजा है। यदि अलग-अलग विकल्प उपलब्ध हों तो यह और बेहतर हो सकता है, लेकिन किसी मेन्यू पर सवाल उठाने और उसे राजनीतिक विचारधारा थोपने का मामला घोषित करने के बीच अंतर है।

इसी तरह, शाकाहारी मेन्यू को भारत की पूरी खाद्य संस्कृति का प्रतिनिधि मान लेना भी सही नहीं होगा। ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा का केंद्र आर्थिक सहयोग, व्यापार, तकनीक और वैश्विक चुनौतियां होनी चाहिए। भोजन पर अपनी राय रखने का अधिकार सबको है, लेकिन एक मेन्यू को राजनीतिक टकराव का विषय बनाने से मूल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं।

केरलम का मामला क्यों चर्चा में?

केरलम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने 24 अक्टूबर को राज्यपाल पद की शपथ ली। उनके कार्यभार संभालने के साथ ही लोकभवन की रसोई में केवल शाकाहारी भोजन तैयार करने का निर्देश चर्चा में आ गया। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना करते हुए इसे व्यक्तिगत खान-पान की स्वतंत्रता से जोड़ा। हालांकि, केरलम के मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस विवाद पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि सीपीआई(एम) के राज्य सचिव एम.वी. गोविंदन ने भोजन की पसंद को व्यक्तिगत मामला बताया। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात निर्देश का वास्तविक दायरा है। वैसे, लोकभवन के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल शाकाहारी हैं।

यह निर्देश उस रसोई के लिए था, जहां उनके और उनके परिवार के लिए भोजन तैयार किया जाता है। कर्मचारियों के अपने खान-पान पर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। कुछ समाचार रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि कर्मचारियों को अपना भोजन घर से लाने या बाहर खाने की स्वतंत्रता है। यदि ऐसा है तो कांग्रेस के महासचिव इसे राजनीतिक रंग क्यों देना चाहते हैं?

पश्चिम बंगाल का मामला

सितंबर में पश्चिम बंगाल में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की दुर्गा पूजा के दौरान मछली-मांस न खाने की अपील पर विवाद हुआ था। कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा के अवसर पर मांसाहारी भोजन से दूर रहने की बात कही और ऐसा करने वालों पर भी टिप्पणी की। उनकी बात का विरोध हुआ, क्योंकि बंगाल में मछली वहां के खान-पान और सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहां भी एक अंतर समझना जरूरी है। किसी धार्मिक वक्ता को शाकाहार के पक्ष में अपनी बात रखने और लोगों से उसका पालन करने की अपील करने का अधिकार है, लेकिन किसी की भोजन संबंधी पसंद को धार्मिकता की कसौटी बनाना अलग बात है। किसी व्यक्ति के भोजन के आधार पर उसे पाखंडी या कम धार्मिक बताना अनावश्यक विवाद पैदा कर सकता है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अपील पर असहमति रखने वालों को भी अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन असहमति का जवाब तर्क से दिया जाना चाहिए, न कि अपमान या हिंसा से। लोकतंत्र में किसी विचार को रखने और उससे असहमत होने, दोनों की जगह है। इस घटना से एक व्यापक सवाल भी सामने आता है। क्या किसी क्षेत्र की परंपराओं को समझे बिना वहां के लोगों को खान-पान के बारे में निर्देश देना उचित है? धार्मिक विचारों का आदान-प्रदान समाज का हिस्सा है, लेकिन किसी एक परंपरा को सबके लिए अनिवार्य मान लेना भारत की विविधता के अनुरूप नहीं है।

आस्था, परिवार और सांस्कृतिक पहचान का विषय

भोजन को लेकर विवाद इसलिए जल्दी बढ़ जाते हैं, क्योंकि यह विषय लोगों की आस्था, परिवार और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। राजनीतिक दल भी कई बार ऐसे मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं, लेकिन जब हर घटना को विचारधारा की लड़ाई बना दिया जाता है तो मूल सवाल पीछे छूट जाता है। शाकाहार अपनाने वाला व्यक्ति अपनी मान्यता और पसंद के अनुसार जीवन जीता है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक विजय कुमार द्वारा ओ.एस. पब्लिकेशन, बी-2542, नरेला, इंडस्ट्रियल एरिया, नार्थ वेस्ट दिल्ली-110040 से मुद्रित कराकर 1536/108 गणेशपुरा रोड, त्रीनगर दिल्ली-110035 से प्रकाशित। सम्पादक : विजय कुमार RNI No. : DELHIN/2015/66886
अखबार में प्रकाशित तथ्यों एवं लेखों से सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं, किसी भी कानूनी वाद विवाद का निपटारा दिल्ली न्यायालय के अधीन होगा। मोबाइल : 9210092542 फोन :- 011-46696546 E-mail : opensearchdelhi@gmail.com

उत्तर प्रदेश कैबिनेट : एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान, चार लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सहमति, 22 प्रस्ताव मंजूर

लखनऊ (एजेंसी)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में पशुधन क्षेत्र को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने से जुड़े प्रस्ताव पर विशेष जोर दिया गया। कैबिनेट में बताया गया कि उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। इसके अलावा अंडा, ऊन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी प्रदेश की स्थिति मजबूत है।

हालांकि, इन क्षेत्रों में मूल्य संवर्धन, डिजिटल प्रबंधन और संगठित बाजार व्यवस्था को बेहतर बनाने की जरूरत है। सरकार का उद्देश्य पशुपालन को किसानों की आय बढ़ाने का प्रमुख माध्यम बनाना है। इसके लिए स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। मिशन के तहत रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने और पशु उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। योजना में उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और गाय की नस्ल सुधारने का भी प्रावधान है। दूध उत्पादन बढ़ाकर प्रति गाय प्रतिदिन 10 लीटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही मुर्गी और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए भी सहायता देने की बात कही गई है।

प्रस्ताव के अनुसार, पशुपालकों को आर्थिक सहायता देने के साथ पशुओं का बीमा भी कराया जाएगा। बीमा की कुल लागत का 85 फीसदी हिस्सा सरकार और 15 फीसदी हिस्सा किसान वहन करेंगे। योजना के तहत एक गाय पर 50 हजार रुपये का अनुदान देने का प्रावधान बताया गया है। सरकार का उद्देश्य पशुपालन क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, बेहतर नस्ल और बाजार व्यवस्था के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में कंपनियों के विलय (मर्जर) और विभाजन (डी-मर्जर) की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए स्टांप ड्यूटी से जुड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया है। स्टांप मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अभी तक प्रदेश में कंपनियों के मर्जर और डी-मर्जर के लिए स्टांप ड्यूटी का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। इसके कारण उद्यमियों को प्रक्रिया के दौरान भ्रम और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मंत्री के मुताबिक, प्रस्ताव के तहत कंपनी के मर्जर या डी-मर्जर में शेयर वैल्यू पर 0.50 फीसदी स्टांप ड्यूटी लगाने का प्रावधान किया गया है।

यदि संबंधित मामले में संपत्ति शामिल है, तो उस पर दो फीसदी स्टांप ड्यूटी का प्रस्ताव है। कंपनी का पंजीकरण कराने और कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेयर वैल्यू के आधार पर स्टांप ड्यूटी देनी होगी। रविंद्र जायसवाल ने कहा कि स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण कई मामलों में सर्किल रेट के बराबर स्टांप ड्यूटी की मांग की जाती थी। इससे कंपनियों के विलय के दौरान उद्यमियों के सामने मुश्किलें आती थीं। प्रस्ताव लागू होने से दो कंपनियों के मिलकर एक कंपनी बनने जैसी प्रक्रियाओं में स्पष्टता आने की उम्मीद है। मंत्री ने बताया कि गुजरात और महाराष्ट्र में इस तरह का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू करने की दिशा में कदम उठाया गया है।

उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी का विषय समवर्ती सूची से जुड़ा होने के कारण प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में जल परिवहन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए नावों और पानी के जहाजों के पंजीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

बनेगी इनलैंड वाटर अथॉरिटी

मंत्री के मुताबिक, जल परिवहन के संचालन और निगरानी के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके अध्यक्ष परिवहन मंत्री होंगे। उन्होंने बताया कि इंजन से चलने वाले बड़े जहाज यांत्रिक श्रेणी में आएंगे, जबकि गांवों में इस्तेमाल होने वाली मोटर चालित छोटी नावों के लिए अलग श्रेणी निर्धारित की जाएगी। नावों का वर्गीकरण यात्रियों की क्षमता के आधार पर भी किया जाएगा। इसमें 10 यात्रियों वाली मोटर नाव, पांच से 10 यात्रियों वाली नाव और पांच तक यात्रियों की क्षमता वाली नाव जैसी श्रेणियां शामिल होंगी।

बिहार : गोपालगंज में बिना योगदान शिक्षिका के खाते में 17.49 लाख रुपये ट्रांसफर

छपरा (एजेंसी)

गोपालगंज जिले में शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मांझा प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय, रूपनछाप कर्णपुरा में शिक्षिका खुशबू कुमारी की नियुक्ति और योगदान को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि बिना वैध योगदान के ही उनके बैंक खाते में वेतन एरियर के रूप में 17 लाख 49 हजार 507 रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। यह राशि बीते 26 मई को उनके खाते में भेजी गई थी। मामला उजागर होने के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

बिना नियुक्ति और योगदान के कैसे हुआ लाखों का भुगतान?

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षिका का योगदान स्वीकार ही नहीं किया गया था, तो उनके नाम पर इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे हुआ। शिक्षा विभाग की स्थापना शाखा ने इस वित्तीय

अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए 13 अक्टूबर को स्कूल के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक मनोज कुमार चौधरी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने सवाल उठाया है कि जब प्रधानाध्यापक ने खुशबू कुमारी का योगदान स्वीकृत नहीं किया था, तो उनके ई-शिक्षा कोष फॉर्म पर हस्ताक्षर कर उसकी एंट्री कराने की अनुमति क्यों और कैसे दी गई।

दस्तावेजों और पंचायत स्तर पर भी गड़बड़ी की पुष्टि

विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार, शिक्षिका का यू-डायस कोड 10151109 और शिक्षक आईडी 1521602 100068 दर्ज है। उनकी नियुक्ति कर्णपुरा पंचायत के नियोजन प्राधिकार द्वारा 4 फरवरी 2016 को जारी आदेश के आधार पर बताई गई है। हालांकि, पंचायत के तत्कालीन मुखिया अवधेश कुमार ने इस तरह की किसी भी नियुक्ति से साफ इनकार किया है। इससे नियोजन पत्र और विभागीय दस्तावेजों की सत्यता और वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीपीओ स्थापना विनय कुमार सुमन ने शिक्षिका खुशबू कुमारी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। पटना हाईकोर्ट के 12 जनवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में डीपीओ कार्यालय द्वारा 21 सितंबर से सुनवाई शुरू की गई थी। शिक्षिका से नियोजन से जुड़े सभी मूल दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 7 अक्टूबर तय की गई थी, लेकिन वह नियत समय पर सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय ने स्पष्ट किया है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच चल रही है।

बिहार : जयप्रभा सेतु के नीचे मिली ओठ कटी नवजात बच्ची, सीएचसी मांझी में भर्ती; पहचान और परिजनों का पता नहीं

सारण (एजेंसी)

बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले जयप्रभा सेतु के नीचे सरयू नदी के तट पर एक नवजात बच्ची मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बच्ची के होंठ कटे हुए हैं। उसे किसने और किन परिस्थितियों में वहां छोड़ा, इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। मामला सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र का है। मंगलवार को जयप्रभा सेतु के नीचे पिलर संख्या-8 के समीप स्थानीय ग्रामीणों की नजर नवजात बच्ची पर पड़ी। बच्ची को इस हालत में देखकर ग्रामीणों ने तत्काल डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बच्ची को अपने साथ लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), मांझी पहुंची। वहां उसे भर्ती कराकर चिकित्सकीय जांच और देखभाल की व्यवस्था की गई। जयप्रभा सेतु बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। ऐसे में पुल के नीचे

मिली नवजात बच्ची के मामले में यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि वह किस राज्य की है। बच्ची को वहां कौन और किन परिस्थितियों में छोड़ गया, यह भी जांच का विषय है। फिलहाल उसकी पहचान और परिजनों के संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। घटना ने नवजात की सुरक्षा और देखभाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जन्म के बाद बच्ची को इस तरह छोड़ने के पीछे क्या परिस्थितियां रहीं, इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल सबसे जरूरी है कि मासूम को समुचित चिकित्सा, सुरक्षा और संरक्षण मिले।

दुलारचंद हत्याकांड : 30 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में अनंत सिंह की जमानत पर सुनवाई

पटना (एजेंसी)

दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना उच्च न्यायालय से मोकामा विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय 30 अक्तूबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता और मृतक के पोते नीरज कुमार ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि उच्च न्यायालय ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। संयोग से 30 अक्तूबर को ही दुलारचंद यादव की पहली बरसी भी है। राज्य सरकार ने भी शीर्ष अदालत में अनंत सिंह के आपराधिक रिकॉर्ड का जिक्र करते हुए उनके खिलाफ दर्ज हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मुकदमों की जानकारी दी है। वर्ष 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 30 अक्तूबर को मोकामा से जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह और जन सुराज

पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों के काफिले आमने-सामने आ गए थे। इस दौरान हुई हिंसा में जन सुराज प्रत्याशी के समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए ही चुनाव में जीत दर्ज की थी। मार्च 2026 में पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आए थे।

जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी पूर्व विधायक नीलम देवी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता भी रद्द करने की अनुशंसा भी की है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने नीलम देवी को 25 नवंबर तक 1, मॉल रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व नीलम देवी को 20 सूत्री समिति से हटाकर राज्य मंत्री का दर्जा भी वापस ले लिया गया। निष्कासन के बाद पार्टी ने बाढ़ संगठनात्मक जिला इकाई को भंग कर दिया। निष्कासन के बाद अनंत सिंह ने जदयू नेतृत्व पर निशाना साधते हुए अपनी नई पार्टी बनाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में निष्कासित करने वालों को परिणाम भुगतना पड़ेगा और जदयू केवल 12 सीटों पर सिमट जाएगी। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस की पूर्व विधायक नीतू सिंह ने अनंत सिंह से मुलाकात की। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी विरोधी काम करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार पार्टी प्रमुख को है।

बिना नाम लिए मायावती ने दी कांग्रेस को नसीहत, कहा-व्यक्तिगत हमले और विषैली राजनीति देशहित में नहीं

लखनऊ (एजेंसी)

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। बसपा प्रमुख ने बिना नाम लिए कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटुता और आरोप-प्रत्यारोप का स्तर अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम हो गया है।

उन्होंने कहा कि इससे देश की गरिमा और मान-मर्यादा पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। पूर्व सीएम मायावती ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'भारतीय राजनीति में आपसी अविश्वास, द्वेष, कटुता और आरोप-प्रत्यारोप का स्तर अब व्यक्तिगत स्तर पर भी काफी बेलगाम हो गया है। यह असंसदीय, अमर्यादित, अपमानजनक, संकीर्ण और जातिवाद से ग्रसित होते हुए हिंसक बयानबाजी तक पहुंच रहा है, जो अति-दुखद और देश की गरिमा व मान-मर्यादा के लिए चिंताजनक है।' उन्होंने कहा कि शीर्ष स्तर पर आसीन लोगों के बीच यदि एक-दूसरे के लिए समुचित सम्मान नहीं है, तो कम से कम आपत्तिजनक और विषैली राजनीति को किसी भी प्रकार से बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। बसपा प्रमुख मायावती के मुताबिक, बढ़ती संकीर्ण और गरीब-विरोधी स्वार्थी राजनीति के कारण लोगों का भरोसा राजनीतिक व्यवस्था पर कमजोर होना देश और जनहित में नहीं होगा। बसपा प्रमुख ने सरकारी स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार और चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन कारणों से जनता पहले से ही बेचैन है।

यूपी चुनाव 2027: मुरादाबाद के कुंदरकी उपचुनाव में भाजपा ने मारी थी बाजी

लखनऊ (एजेंसी)

यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक पार्टियां अपने पक्ष में समीकरण बनाने में जुटी हुई हैं। मुरादाबाद विधानसभा सीटों की स्थिति को देखने के लिए पिछले चुनाव के नतीजों नजर डालना आवश्यक है। पीतलनगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद में विधानसभा की छह सीटें (कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण, मुरादाबाद नगर, कुंदरकी, बिलारी) हैं।

यहां पिछली बार (2022) समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा था, जहां 6 सीटों में चार पर सपा ने जीत दर्ज की थी। दो सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों ने बाजी मारी थी। भाजपा ने एक सीट (कुंदरकी) उपचुनाव में जीती है। कांठः इस सीट पर पिछली बार (2022) समाजवादी पार्टी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। सपा

के कमाल अख्तर ने भाजपा के राजेश कुमार सिंह (चुन्नू) को 43,178 वोटों से हराया था। कमाल अख्तर को 1,34,692 वोट मिले थे। जबकि भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह को 91,514 मत मिले थे। इस सीट पर तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के अफाक अली खां थे। उन्हें 36,341 वोट मिले थे। ठाकुरद्वाराः यहां से पिछली बार (2022) समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। सपा उम्मीदवार नवाब जान ने भाजपा के अजय प्रताप सिंह को 19,684 वोटों से हराया था। सपा के नवाब जान को 134,391 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे भाजपा उम्मीदवार अजय प्रताप सिंह को 114,707 वोट मिले थे।

इस सीट पर तीसरे नंबर पर बसपा के मुजाहिद अली थे। उन्हें 22,163 वोट मिले थे। मुरादाबाद ग्रामीणः इस सीट पर बीते 19 वर्षों से समाजवादी पार्टी का दबदबा है। 2007 के बाद से अब तक हुए चार विधानसभा चुनावों में यहां से सपा ने ही बाजी मारी है। पिछली बार (2022) यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद नासिर कुरैशी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने भाजपा के कृष्णकांत मिश्रा (के.के. मिश्रा) को 56,820 वोटों से हराया था। सपा के मोहम्मद नासिर को 1,43,337 वोट मिले थे।

जबकि भाजपा के के.के. मिश्रा को 86,517 वोट मिले थे। मुरादाबाद नगरः यहां से पिछली बार (2022) भाजपा के रितेश गुप्ता ने सिर्फ 782 वोटों से जीत दर्ज की थी। भाजपा उम्मीदवार ने समाजवादी पार्टी के मो. यूसुफ अंसारी को हराया था। भाजपा के रितेश गुप्ता को 1,48,384 वोट मिले थे। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मो. यूसुफ अंसारी को 147,602 वोट मिले थे। इस सीट पर तीसरे नंबर पर बसपा के इरशाद हुसैन सैफी रहे थे, जिनको 14,013 वोट मिले थे। बिलारीः इस सीट पर पिछली बार (2022) सपा ने बाजी मारी थी।

अयोध्या अपने 10वें भव्य दीपोत्सव के स्वागत को तैयार, रामभक्त फिर बनाएंगे विश्व कीर्तिमान : सीएम योगी

लखनऊ (एजेंसी)

अयोध्या में दीपावली पर दीपोत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या धाम अपने 10वें भव्य-दिव्य दीपोत्सव के स्वागत में पुलकित है। इस वर्ष भी रामभक्त दीप प्रज्वलन का विश्व कीर्तिमान बनाने को तैयार हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा, 'सप्तपुरियों में श्रेष्ठ श्री अयोध्या धाम अपने 10वें भव्य-दिव्य दीपोत्सव के स्वागत में पुलकित है। लाखों दीपों की अलौकिक आभा से जगमगाते सरयू तट, रामायण के प्रसंगों को जीवंत करती मनोहारी झांकियां, भव्य शोभायात्राएं और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां इस महोत्सव में त्रेतायुग की स्मृतियों को फिर से जीवंत करेंगी। हर दीप प्रभु श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा का प्रतीक होगा और हर लौ हमारी सनातन संस्कृति के गौरव का उद्घोष करेगी।' मुख्यमंत्री ने कहा कि किंतु वर्ष 2017 से पहले प्रभु श्री राम की प्राणप्रिय नगरी अयोध्या जी उपेक्षा, अव्यवस्था और बदहाली का दंश झेल रही थीं। निर्दोष रामभक्तों पर गोलियां चलवाने वाली और पवित्र श्री हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप करने वाली सरकार को 'राम की अयोध्या' के विकास से क्या मतलब? प्रभु श्री राम की कृपा से वर्ष 2017 के बाद श्री अयोध्या जी में विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का नया सूर्योदय हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार के प्रयासों से रामनगरी अपने प्राचीन वैभव को पुनः प्राप्त कर रही है। भव्य-दिव्य श्री राम मंदिर, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सुसज्जित रामपथ, नव्य घाट, आधुनिक सुविधाएं और सोलर सिटी के रूप में विकसित होती अयोध्या आज आस्था और आधुनिकता की अद्भुत संगम स्थली बन चुकी है।

बिहार : खरगे के बयान पर भाजपा को तूल देने का आरोप, तेजस्वी बोले- बिहार के असल मुद्दों से ध्यान भटका रही पार्टी

मुज्जफरपुर (एजेंसी)

वैशाली जिले के बिदुपुर पहुंचे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की विवादित टिप्पणी पर जारी सियासत के बीच भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है और बात का बतंगड़ बना रही है।

भाजपा को बिहार के लोगों की असल समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा का ध्यान न तो रोजगार पर है, न कमाई पर, न दवाई पर, न पढ़ाई पर और न ही सिंचाई पर। भाजपा सिर्फ बयानबाजी कर लोगों का ध्यान

भटकाना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने बिहार में बिगड़ती कानून-व्यवस्था, बढ़ते अपराध और बेरोजगारी को लेकर नीतीश सरकार और एनडीए सरकार को घेरा।

उन्होंने कहा कि आज बिहार में अपराध चरम पर है। हर दिन हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार खामोश है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं और पलायन करने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार के पास रोजगार देने की कोई ठोस योजना नहीं है। बिहार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और खजाने की स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने सरकार की आर्थिक नीतियों को पूरी तरह विफल बताया।

डबल इंजन सरकार फेल : तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने डबल इंजन सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार है, फिर भी बिहार को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए क्या किया? उन्होंने कहा कि बिहार हर साल बाढ़ से तबाह होता है। लाखों लोग बेघर होते हैं और किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, लेकिन केंद्र सरकार बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करती और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा तक नहीं मिलता। किसान परेशान हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आते ही भाजपा डबल इंजन सरकार और विकास के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन बिहार को आज तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। विशेष पैकेज के नाम पर भी बिहार को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ चुनाव के समय बिहार की जनता को ठगने का काम करती है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, किसानों की समस्या और बाढ़ से निजात जैसे बुनियादी मुद्दों पर भाजपा कभी गंभीर नहीं रही। मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बिहार की जनता को रोजगार, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए, लेकिन भाजपा बयानबाजी कर मुद्दों से ध्यान हटा रही है।

दुकान बंद कर घर लौट रहे स्वर्ण व्यवसायी की हत्या

समस्तीपुर (एजेंसी)

समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में सोमवार देर रात बाइक सवार बदमाशों ने एक स्वर्ण व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। काली चौक स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे राजेश कुमार पोद्दार को दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के पगड़ा गांव के वार्ड संख्या नौ में काली स्थान के समीप निशाना बनाया गया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखे और एक गोली बरामद की है।

हत्या के पीछे लूटपाट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, फिलहाल वारदात की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। मृतक की पहचान दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के घाट नवादा निवासी राजकुमार पोद्दार के पुत्र राजेश कुमार पोद्दार के रूप में हुई है। राजेश की दलसिंहसराय के काली चौक पर स्वर्ण आभूषण की दुकान थी। बताया जाता है कि सोमवार रात दुकान बंद करने के बाद वह पगड़ा गांव के वार्ड संख्या 13 स्थित अपने नवनिर्मित मकान लौट रहे थे। इसी दौरान काली स्थान के समीप बाइक सवार बदमाशों ने पीछे से उन पर गोली चला दी। गोली लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

उत्तर रेलवे

सूचना

दिनांक 08.11.2026 (रविवार) दीपावली के उपलक्ष्य में दिल्ली क्षेत्र के आरक्षण कार्यालय जो कि मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक/यात्री विपणन के अधीन कार्यरत हैं, उनके कार्य करने हेतु निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं:–

(ए) आंशिक सेवा:–

(1) आई0आर0सी0ए0 भवन (2) दिल्ली जंक्शन व (3) हजरतनिजामुद्दीन आरक्षण कार्यालयों में सायंकालीन पारी में आंशिक सेवायें 18:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।

(बी) सायंकालीन पारी में निम्न आरक्षण केन्द्र बन्द रहेंगे:–

(1) सरोजनीनगर (2) कीर्तिनगर (3) शकूरबस्ती (4) दिल्लीशाहदरा (5) गाजियाबाद (6) कड़कड़डूमा (7) ओखला (8) नोएड़ा (9) तुगलकाबाद (10) सब्जीमण्डी (11) आदर्श नगर (12) लाजपत नगर (13) रोहिणी (14) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) (15) अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो (आई0आर0सी0ए0 भवन)

उपरोक्त सभी कार्यालय प्रात: कालीन पारी में यथावत कार्यरत रहेंगे।

(सी) निम्नलिखित आरक्षण केन्द्र पूरे दिन बन्द रहेंगे:–

(1) संसद भवन (2) प्रेस–क्लब आफ इण्डिया (3) रेलवे बोर्ड (4) सुप्रीम कोर्ट (5) हाई कोर्ट (6) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

3739/2026 — उप मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/आईटी

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

नॉर्थ डकोटा के निवासी बोले-ट्रंप ने अमेरिका को अंदर से सुरक्षित बनाया, ग्लोबल स्तर पर खतरा बरकरार

वाशिंगटन (एजेंसी)

यह बात मध्यावधि चुनावों से पहले व्हाइट हाउस के बाहर नॉर्थ डकोटा के चौथी पीढ़ी के एक किसान रेजिनाल्ड हरमन ने कही। उन्होंने ट्रंप से 'थोड़ा नरम' व्यवहार अपनाने और 'अधिक स्वतंत्र व्यापार' को बढ़ावा देने की भी अपील की। जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप ने अमेरिका को सुरक्षित बनाया है, तो हरमन ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर शायद नहीं क्योंकि ईरान के साथ टकराव कुछ खतरे पैदा कर सकता है

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश को अंदरूनी तौर पर ज्यादा सुरक्षित बनाया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है। यह बात मध्यावधि चुनावों से पहले व्हाइट हाउस के बाहर नॉर्थ डकोटा के चौथी पीढ़ी के एक किसान रेजिनाल्ड हरमन ने कही। उन्होंने ट्रंप से 'थोड़ा नरम' व्यवहार अपनाने और 'अधिक स्वतंत्र व्यापार' को बढ़ावा देने की भी अपील की।

जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रंप ने अमेरिका को सुरक्षित बनाया है, तो हरमन ने कहा, 'वैश्विक स्तर पर शायद नहीं क्योंकि ईरान के साथ टकराव कुछ खतरे पैदा कर सकता है। लेकिन देश के भीतर की बात करें तो बिल्कुल, हां। 'डेविल्स लेक जर्नल' में छपे उनके परिवार के इतिहास के अनुसार, हरमन नॉर्थ डकोटा के छोटे से शहर 'ब्रिंसमेड' के रहने वाले हैं, जो ग्रैंड फोर्क्स से लगभग 100 मील पश्चिम में स्थित है। वे 'हरमंसडेल फार्म' चलाते हैं, जिस पर उनका परिवार 1901 से खेती करता आ रहा है। ट्रंप के लिए उनका संदेश छोटा लेकिन सीधा था। उन्होंने कहा, फ्रैंकलिन ग्राहम की बात सुनिए और थोड़ा नरम बनिए, लेकिन साथ ही मजबूत, दृढ़ और सख्त भी रहिए। हरमन ने कहा कि इमिग्रेशन का मुद्दा उनके राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है, भले ही इसे अक्सर केवल सीमा वाले राज्यों का विषय माना जाता है। उन्होंने कहा, 'यकीन मानिए, नॉर्थ डकोटा में भी इमिग्रेशन का मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।' हालांकि, उन्होंने सुरक्षित सीमाओं और प्रवासियों के प्रति नफरत के बीच साफ अंतर बताया।

उन्होंने कहा, मैं सुरक्षित सीमाओं के पक्ष में हूं, लेकिन मैंने एक एशियाई लड़की को गोद लिया है। मुझे प्रवासी लोगों से प्यार है। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि यह प्रक्रिया सुरक्षित और सही तरीके से होनी चाहिए, जैसा मेरे दादाजी ने किया था और जैसा मेरे कई प्रवासी दोस्तों ने किया है। हरमन ने बताया कि उनके परिवार ने दूसरे देशों के चार लोगों को ग्रीन कार्ड या यूक्रेनी नागरिकों के लिए बनाए गए कार्यक्रम के जरिए अमेरिका आने में मदद की। उन्होंने कहा, हम एक-दो परिवारों को यहां लेकर आए और युद्ध से बचने के लिए अमेरिका आने में उनका सहयोग किया। इसलिए हम इमिग्रेशन का समर्थन करते हैं, बस चाहते हैं कि यह सही तरीके से हो। कृषि क्षेत्र की बात करते हुए हरमन ने कहा कि किसान सरकारी नियमों के आदी हैं, लेकिन वे ज्यादा खुले व्यापार की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां काफी सरकारी नियम हैं, इसलिए हमें सरकार की भागीदारी की आदत है। लेकिन साथ ही हम ज्यादा स्वतंत्र व्यापार भी देखना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि उनके बच्चे और पोते-पोतियां, जो उनके परिवार की पांचवीं और छठी पीढ़ी हैं, आगे बढ़ने की आजादी पाएं, उन पर उचित कर लगे, लेकिन उन पर जरूरत से ज्यादा पाबंदियां न हों। ट्रंप के दोबारा सत्ता में लौटने के बाद के पहले दो वर्षों को लेकर हरमन की राय मिली-जुली रही। उन्होंने कहा, कुछ बातें मुझे पसंद हैं और कुछ नहीं। ऐसा तो मेरे जन्म के बाद लगभग हर राष्ट्रपति के साथ रहा है, जॉन एफ. कैनेडी के समय से। उन्होंने कहा, काश ट्रंप थोड़ा नरम स्वभाव के होते, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि वॉशिंगटन में अगर आप बहुत नरम हैं, तो लोग आपको दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर भी पिछले दो सालों में काफी काम हुआ है। हरमन ने व्हाइट हाउस में बनाए जा रहे नए बॉलरूम प्रोजेक्ट की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, यह बॉलरूम मुझे गर्व महसूस कराता है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक व्हाइट हाउस में विश्वस्तरीय और सुरक्षित सुविधाएं होनी ही चाहिए। उन्होंने राजनीतिक गतिरोध के लिए दोनों प्रमुख दलों को जिम्मेदार ठहराया। हरमन ने कहा, मुझे लगता है कि यह लड़ाई पूरी तरह राजनीतिक है और दोनों पक्ष इसमें शामिल हैं। यह सिर्फ एक पार्टी की समस्या नहीं है। दोनों ही कुछ हद तक अपरिपक्व व्यवहार करते हैं।

वोटर धोखाधड़ी की जानकारी देने वालों को एक मिलियन डॉलर इनाम देंगे ट्रंप

वाशिंगटन (एजेंसी)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों से कुछ दिन पहले एक मिलियन डॉलर देने की अनोखी घोषणा की है। उनके अनुसार, जो व्यक्ति वोटर धोखाधड़ी की ऐसी जानकारी देगा, जिसके आधार पर किसी की गिरफ्तारी और सजा होगी, उसे यह इनाम दिया जाएगा। सोमवार को एयरफोर्स वन में सवार होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, 'मैं एक मिलियन डॉलर का बोनस या इनाम देने जा रहा हूं। जो भी व्यक्ति वोटर धोखाधड़ी की जानकारी देगा और उसकी वजह से किसी की गिरफ्तारी तथा सजा होगी, उसे एक मिलियन डॉलर दिए जाएंगे।'

बातचीत के दौरान एक पत्रकार ने ट्रंप से कहा कि उन्होंने पहले स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कोई गैर-अमेरिकी नागरिक मतदान करता है, तो उसे स्वतः निर्वासित (डिपोर्ट) कर दिया जाएगा। पत्रकार ने पूछा कि क्या इससे चुनावी व्यवस्था बेहतर होगी और क्या इस संदेश को उनकी सभी चुनावी रैलियों में दोहराया जाना चाहिए। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि हां, हम ऐसा कर रहे हैं और हमने उस प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी है। हालांकि, व्हाइट हाउस ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इनाम की राशि किस तरह दी जाएगी, कौन सी एजेंसी इसका संचालन करेगी या इसके लिए कानूनी आधार क्या होगा। अमेरिका में संघीय चुनावों में गैर-नागरिकों की ओर से मतदान करना पहले से ही एक संघीय अपराध है।

मौजूदा कानून के तहत ऐसा करने पर जुर्माना, जेल और देश से निष्कासन जैसी सजा हो सकती है। ट्रंप की यह टिप्पणी अमेरिका में रहने वाले प्रवासी समुदायों का ध्यान खींच सकती है, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग भी शामिल हैं। ग्रीन कार्ड धारक और अस्थायी कार्य वीजा पर रहने वाले भारतीय नागरिक संघीय चुनावों में मतदान करने के पात्र नहीं होते।

रूस और यूक्रेन की सहमति से ओलेश्की में सीज फायर, मानवीय मिशन चालू

कीव (एजेंसी)

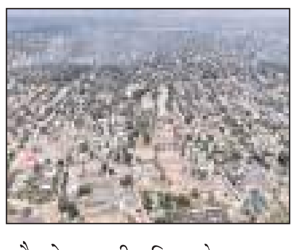

रूस और यूक्रेन ने मंगलवार को ओलेश्की शहर में मानवीय सहायता कार्य शुरू करने के लिए एक 'क्षेत्रीय संघर्ष विराम' लागू कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रमुख किरिलो बुडानोव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। हालांकि, अन्य जगहों पर, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है, हमले अभी भी जारी हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के करीबी और कार्यालय प्रमुख बुडानोव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया,' ओलेश्की में एक महत्वपूर्ण मानवीय मिशन शुरू हो गया है। जिस इलाके में यह मिशन चल रहा है, वहां दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम की घोषणा की गई है।' उन्होंने आगे कहा कि यूक्रेनी संसद के आयुक्त, दमित्रो लुबिनेट्ज मौके पर पहुंच गए हैं और वे इस पूरी प्रक्रिया के समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हम लगातार उनके संपर्क में हैं। बुडानोव ने इसे मिशन की कामयाबी को आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमारे लोगों को बचाने का यह मिशन सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से पूरा हो।

इस अभियान को चलाने और इसमें सहयोग देने वाले सभी लोगों का मैं दिल से आभारी हूं। इससे पहले मानवाधिकारों के लिए संसदीय आयुक्त दमित्रो लुबिनेट्से ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने बताया कि यूक्रेन की टीम के प्रमुख के तौर पर, वे यह कह सकते हैं कि यूक्रेनी पक्ष अपने वादों का पालन कर रहा है। उन्होंने रूस द्वारा संघर्ष विराम (गोलाबारी रोकने) के समय की भी पुष्टि की। टेलीग्राम पर, रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन के खेरसॉन शहर की दिशा में सुबह 4 बजे (मॉस्को समय, 0100 जीएमटी) से गोलाबारी रोक दी है। ऐसा ओलेश्की में की जाने वाली तैयारियों के लिए किया गया है, जो नीपर नदी के उस पार खेरसॉन के सामने स्थित है। लुबिनेट्से ने आगे बताया कि यह समझौता रूस की मानवाधिकार आयुक्त याना लांत्रतोवा के सहयोग से और अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप की मदद से संभव हो पाया है।

भारत ने यूएनएससी में 'डी फैक्टो वीटो' पर उठाए सवाल

न्यूयॉर्क (एजेंसी)

महासभा में पांच स्थायी सदस्यों (पी5) के वीटो अधिकारों पर हुई बहस के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने बताया कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए 'इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन्स' (आईजीएन) के तहत यह एक अहम मुद्दा था, लेकिन कुछ देशों ने 'अप्रत्यक्ष वीटो' का इस्तेमाल किया जिससे ये प्रक्रिया अटक गई है

भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में वीटो को लेकर अपना मत स्पष्ट किया है। भारतीय प्रतिनिधि ने 'डी फैक्टो वीटो' की आलोचना करते हुए कहा कि वीटो अधिकार का नहीं बल्कि जिम्मेदारी का एहसास कराता है।

सोमवार को महासभा में पांच स्थायी सदस्यों (पी5) के वीटो अधिकारों पर हुई बहस के दौरान, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी. हरीश ने बताया कि सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए 'इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन्स' (आईजीएन) के तहत यह एक अहम मुद्दा था, लेकिन कुछ देशों ने 'अप्रत्यक्ष वीटो' का इस्तेमाल किया जिससे ये प्रक्रिया अटक गई है।

उन्होंने कहा, आईजीएन प्रक्रिया में भी 'आम सहमति' की दलील का इस्तेमाल एक डी फैक्टो वीटो (छिपे हुए) के रूप में किया जा रहा है। भारत के अनुसार, वीटो पावर का विशेषाधिकार किसी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ को साधने का साधन नहीं बनना चाहिए। 'यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस' नाम के देशों के एक छोटे समूह ने प्रक्रिया संबंधी पैंतरों का इस्तेमाल करके आईजीएन को बातचीत के लिए कोई मसौदा अपनाने से रोक दिया है। इस समूह का नेतृत्व इटली कर रहा है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। हरीश ने कहा कि 2008 का महासभा प्रस्ताव, जो आईजीएन के लिए आधारभूत निर्णय है, बिल्कुल स्पष्ट हैः इसका मुख्य सिद्धांत 'अधिकतम राजनीतिक स्वीकृति' है, न कि 'आम सहमति'। उन्होंने बताया कि बातचीत के 17 दौर पूरे होने के बाद भी, 'हमारे पास दिखाने के लिए कोई नतीजा नहीं है।' इसका कारण वह 'व्यावहारिक वीटो' है, जिसका आईजीएन को बनाने वाले प्रस्ताव में कोई आधार नहीं है।

उन्होंने कहा कि व्यापक सुधारों की शुरुआत के लिए 'स्पष्ट समय-सीमा और लक्ष्यों के साथ, मसौदे पर आधारित बातचीत को जल्द शुरू करना' जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसे गुप्त वीटो भी हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मान्यता नहीं मिली है, फिर भी कुछ अहम मामलों में गैर-स्थायी सदस्यों को भी इनका इस्तेमाल करने दिया जाता है। इस ओर इशारा करते हुए हरीश ने कहा, वीटो सिर्फ वह नहीं है जिसका इस्तेमाल खुले तौर पर किया जाता है। इसके अलावा एक डी फैक्टो वीटो भी होता है, जो सुरक्षा परिषद के हर सदस्य–चाहे वह चुना गया हो या नहीं–के पास होता है।

इसका इस्तेमाल वे अध्यक्षीय बयानों, प्रेस बयानों और प्रतिबंध समितियों के फैसलों पर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आम सहमति के 'अलिखित नियम' के तहत, कोई भी एक सदस्य किसी प्रस्ताव को रोक सकता है, और अक्सर इसके लिए उसे कोई कारण भी नहीं बताना पड़ता।

अर्नब चक्रवात की आशंका को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश

महासमुंद (एजेंसी)

अर्नब चक्रवात की आशंका को देखते हुए महासमुंद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 से 29 अक्टूबर तक चक्रवात का प्रभाव पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने आज समय-सीमा की बैठक में सभी विभागों को सतर्क रहने तथा आवश्यक एहतियाती तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आपदा की स्थिति में जनहानि और पशुहानि रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को आपात स्थिति से निपटने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर तैयार रखने, पुलिस विभाग को सतर्क रहने तथा विद्युत विभाग को संभावित व्यवधानों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीआरएफ एवं होमगार्ड के जवानों को भी आवश्यकतानुसार तैनात रखने और सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया। आपदा संबंधी सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान और राहत कार्यों के समन्वय के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

आम नागरिक किसी भी आपात स्थिति में 07723-223305 पर संपर्क कर सकते हैं। कलेक्टर ने सभी तहसीलों में भी कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। कलेक्टर श्री लंगेह ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आम नागरिकों तक समय पर आवश्यक जानकारी पहुंचाने के लिए कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराने के निर्देश दिए।

तमिलनाडु : फिल्मी स्टाइल में थेनी जेल के सुरक्षा गार्डों पर हमला कर भागे 17 कैदी, 4 पकड़े गए

थेनी (एजेंसी)

तमिलनाडु के थेनी जिले में एंडिपट्टी के पास थेक्कम्पट्टी जिला जेल से सोमवार रात 17 कैदी जेल प्रहरियों पर हमला करके भाग निकले। फरार कैदियों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया है। मंगलवार सुबह तक चार कैदियों को फिर से पकड़ लिया गया जबकि बाकी 13 कैदियों की तलाश जारी है। शुरुआती जांच से पता चला है कि एक कैदी ने दौरा पड़ने का नाटक किया, जिससे गार्ड उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए अंदर आ गए।

मदद के लिए आए गार्डों पर कैदियों ने हमला कर दिया और एक साथ भाग निकले। इस तरह, एक मेडिकल इमरजेंसी को उन्होंने जेल से भागने के मौके में बदल दिया। इस हमले में घायल हुए एक जेल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना सोमवार रात 10 बजे हुई। सूचना मिलने पर थेनी के पुलिस अधीक्षक प्रवीण गौतम तुरंत जेल पहुंचे और वहां का मुआयना किया। दक्षिणी क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजयेन्द्र बिदारी ने भी जेल का दौरा किया और जेल कर्मचारियों से भागने की घटना के बारे में पूछताछ की। आईजी बिदारी ने मीडिया को बताया कि पुलिस को रात 10:20 बजे कैदियों के भागने की सूचना मिली। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए 17 विशेष टीमें बनाई गई हैं और पूरे जिले में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहीं, सबसे पहले पकड़े गए कैदी का नाम प्रवीण है, जो मदुरै जिले के पेरुंगुडी का रहने वाला है। पुलिस को वह जेल के पास एक जंगली इलाके में मिला, जिसके बाद उसे वापस हिरासत में ले लिया गया।

जांचकर्ताओं ने उससे भागने की योजना और कैदियों के अगले ठिकाने के बारे में पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में पता चला कि गार्डों को झांसे में लाने के लिए कैदी ने दौरा पड़ने का नाटक किया था। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि कैदियों ने हमले की योजना कैसे बनाई और वे जेल परिसर से बाहर निकलने में कैसे कामयाब रहे। मंगलवार सुबह पुलिस ने थेनी जिले के देवराम के रहने वाले सिलंबरासन को पकड़ लिया। इसके बाद राजकुमार और राजा सिकंदर को भी पकड़ लिया गया जिससे पकड़े गए कैदियों की कुल संख्या चार हो गई। जेल से कैदियों के भागने के बाद पुलिस ने पूरे थेनी जिले में वाहनों की जांच तेज कर दी है। फरार कैदियों का पता लगाने के लिए खोजी कुत्तों (स्निफर डॉग्स) की मदद ली जा रही है और जेल के आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। थेक्कम्पट्टी जेल में थेनी, मदुरै, डिंडीगुल और अन्य इलाकों के विचाराधीन कैदी (अंडरट्रायल) रखे जाते हैं। बताया जा रहा है कि भागने वालों में से ज्यादातर मदुरै जिले के विचाराधीन कैदी थे। इनमें से तीन पर 'गुंडा एक्ट' के तहत कार्रवाई की जानी थी।

अमृतसर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई : 7 आरोपी गिरफ्तार, 14 अत्याधुनिक पिस्तौल और 20 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर (एजेंसी)

अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 अत्याधुनिक पिस्तौल और 20 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। पंजाब पुलिस के डीजीपी कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस कार्रवाई को अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी कथित तौर पर विदेश में बैठे एक हैंडलर के संपर्क में थे। जांच एजेंसियों को संदेह है कि इस हैंडलर की मदद से अवैध हथियारों की खेप मंगवाई जाती थी और फिर उन्हें संगठित नेटवर्क के जरिए आपराधिक तत्वों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कार्यप्रणाली, हथियारों की सप्लाई के स्रोत और आरोपियों के अन्य संभावित संपर्कों का पता लगाने में जुटी है। इस मामले में घरिंडा और कथूनंगल पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस की ओर से आरोपियों से पूछताछ और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है, ताकि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा सके। जांच का मुख्य उद्देश्य हथियारों और हेरोइन की सप्लाई के पीछे सक्रिय लोगों तक पहुंचना तथा नेटवर्क के आगे और पीछे के संपर्कों का पता लगाना है। पंजाब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अवैध हथियारों, नशा तस्करी और संगठित अपराध के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अमृतसर ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई से सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय अवैध हथियारों और नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की

त्रिपुंड, त्रिनेत्र और चंद्रमा से रजत मुकुट में सजे बाबा महाकाल, दर्शन को उमड़े भक्त

उज्जैन (एजेंसी)

शृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा

विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और द्वितीया तिथि मंगलवार की सुबह 4 बजे हुई भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन-अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया।

श्रृंगार के बाद बाबा महाकाल को भस्म रमाई गई। इस दौरान भक्तों ने इन दिव्य दर्शनों का लाभ लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से मंदिर परिसर गूंज उठा। मंदिर के पुजारी पंडित महेश शर्मा ने बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रथमा द्वितीया तिथि मंगलवार पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान भस्म आरती के लिए सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलते ही पण्डे पुजारियों ने गर्भगृह में स्थापित सभी भगवान की प्रतिमाओं का पूजन कर भगवान महाकाल का जलाभिषेक दूध, दही, घी, शक्कर फलों के रस से बने पंचामृत को अर्पित कर किया। इसके बाद प्रथम घंटाल बजाकर हरि ओम का जल अर्पित किया गया। कपूर आरती के बाद बाबा महाकाल को चांदी का मुकुट और मुंड माला धारण करवाई गई। मंगलवार के श्रृंगार की विशेष बात यह रही कि आज बाबा महाकाल का त्रिपुंड, त्रिनेत्र और चन्द्रमा से श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा महाकाल को रजत मुकुट भी पहनाया गया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में बड़ी संख्या मे श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने बाबा महाकाल के इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होकर जय श्री महाकाल का उद्घोष करने लगे। मान्यता है कि भस्म अर्पित करने के बाद भगवान निराकार से साकार स्वरूप में दर्शन देते हैं।

महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन और शिक्षाएँ हमें समानता, सामाजिक समरसता, करुणा एवं मानवता का संदेश देती हैं : धामी

ओपन सर्च/ओ पी उनियाल

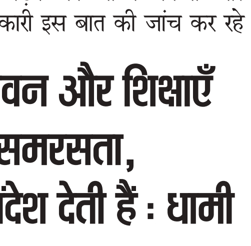

देहरादून। महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव के अवसर पर देहरादून में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन द्वारा भव्य शोभायात्रा निकाली गयी। शोभायात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामायण के रचयिता, आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जी को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन और शिक्षाएँ हमें समानता, सामाजिक समरसता, करुणा एवं मानवता का संदेश देती हैं। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार समाज के प्रत्येक वर्ग के सम्मान, कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा हमारी सरकार सफाई कर्मियों के योगदान और उनके परिश्रम का सम्मान करते हुए उनके हितों के प्रति संवेदनशील है। इसी दिशा में प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत सफाई कर्मियों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में बैठक कर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। इस अवसर पर मेयर, देहरादून सौरभ थपलियाल, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना, उत्तराखंड सरकार में दर्जाधारी राज्यमंत्री अशोक वर्मा, श्याम अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ उमेश अग्रवाल, गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारीगण एवं वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन के चलते शहर के मुख्य मार्गों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और यातायात डायवर्जन लागू किया गया था ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

आध्यात्मिक जागृति की अविरल सरिता में सम्पन्न हुआ 79वाँ निरंकारी संत समागम

ओपन सर्च. संवाददाता

समालखा। 'ब्रह्मज्ञान की वास्तविक सार्थकता उसे जीवन में अपनाने और अपने विचारों, व्यवहार एवं कर्मों में शामिल करने में है।' ये दिव्य भाव सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 79वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के समापन दिवस पर लाखों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को अपने पावन आशीर्वचनों द्वारा प्रदान किए। जागृति' की आध्यात्मिक प्रेरणाओं को अपने जीवन में आत्मसात कर स्वयं के उत्थान के साथ-साथ जगत कल्याण की भावना को सुदृढ़ करने वाला यह पावन संत समागम कल रात्रि प्रेमभक्ति एवं श्रद्धा से ओतप्रोत वातावरण में संपन्न हुआ। समागम से आध्यात्मिक प्रेरणा और मधुर स्मृतियां लेकर श्रद्धालु भक्तजन धीरे-धीरे अपने-अपने गंतव्यों की ओर प्रस्थान करने लगे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने विशाल मानव परिवार को सम्बोधित करते हुए अपने पावन प्रवचनों में फरमाया कि 'जागृति' केवल सत्संग या समागम तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में निराकार परमात्मा के अहसास के साथ जीने का नाम है। ब्रह्मज्ञान की वास्तविक सार्थकता तभी है, जब हम इसे अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों में अपनाएं।

सतगुरु माता जी ने सकारात्मक सोच, प्रेम, करुणा और विनम्रता अपनाने तथा दूसरों की कमियों के बजाय उनकी खूबियों को देखने की प्रेरणा दी। सच्ची जागृति का आरंभ अपने घर-परिवार और निजी जीवन से होता है। सेवा, सुमिरन और सत्संग को जीवन का अभिन्न अंग मानकर हर परिस्थिति में परमात्मा का एहसास बनाए रखना ही जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाता है। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के सचिव आदरणीय श्री जोगिंदर सुखीजा ने सतगुरु माता जी एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन दर्शन कर उनके दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। साथ ही, समस्त साध-संगत तथा समागम के सफल आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सरकारी विभागों का हार्दिक आभार प्रकट किया। उन्होंने इस वर्ष समागम में पिछले वर्षों की अपेक्षा अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की और भविष्य में भी संगत की संख्या में निरंतर वृद्धि होने की मंगलकामना की।

20 बाउंड्री के साथ कूटे 113 रन, न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने लगाई 'रिकॉर्ड्स की झड़ी'

वेलिंगटन (एजेंसी)

भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मंगलवार को हेनरी स्टेडियम में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में 113 रन बनाए। 38 गेंदों की पारी में अभिषेक ने 11 छक्के और 9 चौके लगाए। इस दौरान उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ 7.1 ओवरों में 133 रन की साझेदारी की। इस पारी के साथ अभिषेक ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। यह टी20 क्रिकेट में अभिषेक शर्मा का 11वां शतक था।

इस लिस्ट में क्रिस गेल शीर्ष पर हैं, जिन्होंने अपने करियर में कुल 22 शतक लगाए। वहीं, बाबर आजम (13) इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। क्विंटन डी कॉक (10), विराट कोहली (10) और डेविड वॉर्नर (10) संयुक्त रूप से चौथे पायदान पर मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इस लिस्ट में ग्लेन मैक्सवेल और रोहित शर्मा संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं, जिन्होने 5-5 शतक लगाए हैं। करनबीर सिंह, फिल सॉल्ट, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा इस लिस्ट में 4-4 शतकों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं।

फुल-मेंबर टीमों की तरफ से सबसे तेज शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में अभिषेक (30 गेंदें बनाम अफगानिस्तान, 2026) पहले ही शीर्ष पायदान पर थे, लेकिन न्यूजीलैंड के विरुद्ध वेलिंगटन में 35 गेंदों में शतक लगाकर इस लिस्ट में अभिषेक संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर भी शामिल हो गए हैं। उनके अलावा, डेविड मिलर (बनाम बांग्लादेश, 2017) और रोहित शर्मा (बनाम श्रीलंका, 2017) 35-35 गेंदों में यह कारनामा कर चुके हैं। सिकंदर रजा (33 गेंदें बनाम गाम्बिया, 2024) इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में अपनी पहली ही गेंद पर छक्का लगाया। अभिषेक (8 बार) टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार पहली गेंद पर छक्का लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले पायदान पर हैं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान के शफीकुल्लाह शिनवारी (6 बार), जबकि सूर्यकुमार यादव (5 बार) तीसरे स्थान पर मौजूद हैं। अभिषेक शर्मा ने इस मैच में सिर्फ 15 गेंदों अर्धशतक पूरा किया।

इससे पहले अभिषेक 14 गेंदों में न्यूजीलैंड के विरुद्ध गुवाहाटी में यह कारनामा कर चुके हैं। दो फुल-मेंबर टीमों के बीच टी20 मुकाबले के दौरान सबसे तेज 'पचासा' जड़ने के रिकॉर्ड युवराज सिंह (बनाम इंग्लैंड, 2007) के नाम है, जिन्होंने 12 गेंदों में यह कारनामा किया था। अभिषेक ने इस मुकाबले के दौरान 11 छक्के लगाए। इससे पहले अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ साल 2025 में एक ही पारी में 13 छक्के लगा चुके थे। साल 2026 में उन्होंने अफगानिस्तान के विरुद्ध 11 छक्के जड़ने का कारनामा किया था। भारत के लिए टी20 पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा और ईशान किशन उनसे पीछे हैं, जिन्होंने एक ही टी20 पारी में 10-10 छक्के जड़े।

अभिषेक पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में दूसरे पायदान पर हैं। उनसे आगे ऑस्ट्रिया करनबीर सिंह (5 बार) हैं। वहीं, पुरुष टी20 मुकाबलों में सबसे ज्यादा बार एक पारी में 10 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में अभिषेक (7 बार) दूसरे पायदान पर हैं, जबकि क्रिस गेल (18) लिस्ट में शीर्ष पर हैं। वैभव सूर्यवंशी और करनबीर सिंह (5-5 बार) इस लिस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे पायदान पर हैं।

अभिषेक के तूफानी शतक और वैभव की आतिशी पारी से भारत की जीत

भारत ने तीसरे टी-20 मुकाबले में न्यूजीलैंड को 6 विकेट से करारी शिकस्त देकर पांच मैचों की सीरीज अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड की ओर से मिले 199 रन के लक्ष्य को टीम इंडिया ने महज 13.2 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में ऐसी बढ़त बना ली है कि अब न्यूजीलैंड के पास वापसी के लिए केवल दो मुकाबले बचे हैं। भारतीय टीम की इस शानदार जीत के हीरो अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी रहे। अभिषेक ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए

सिर्फ 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह उनके टी-20 इंटरनेशनल करियर का चौथा शतक रहा। वहीं, युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 19 गेंदों पर 45 रन की तेजतर्रार पारी खेलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की आक्रामक बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम ने दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। भारत ने महज 5 ओवर में 100 रन पूरे कर लिए, जो टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज टीम शतक है। इसके अलावा, टीम इंडिया ने पावरप्ले में भी इतिहास रच दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआती 6 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 118 रन बना दिए। इस दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों की रफ्तार पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 198 रन बनाए थे।

तीसरा टी20 : भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया, सीरीज पर किया कब्जा

वेलिंगटन (एजेंसी)

भारत ने हेनरी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया है। भारतीय टीम को जीत के लिए 199 रन का लक्ष्य मिला था। अभिषेक शर्मा के विस्फोटक शतक के दम पर टीम इंडिया ने 13.2 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली है। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा उतरे।

बाएं हाथ के दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि पावर प्ले का नया रिकॉर्ड बन गया। वैभव और अभिषेक ने 6 ओवर के पावर प्ले में 118 रन बनाए। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावर प्ले का यह विश्व रिकॉर्ड है। इन 118 रनों में वैभव ने 17 गेंदों पर 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए, जबकि अभिषेक ने 20 गेंदों पर 7 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 67 रन का योगदान दिया। भारत को पहला झटका 133 के स्कोर पर लगा।

वैभव सूर्यवंशी 19 गेंदों पर 45 रन बनाकर आउट हुए। अभिषेक शर्मा ने अपने अंतरराष्ट्रीय टी20 करियर का चौथा शतक लगाया। अभिषेक ने 38 गेंदों पर 11 छक्कों और 9 चौकों की मदद से 113 रन की पारी खेली। वह 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर 178 के स्कोर पर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर 5 और सैमसन 18 रन बनाकर आउट हुए। भारत ने 13.2 ओवर में 4 विकेट पर 199 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीता। नमन धीर 4 और तिलक वर्मा 1 रन बनाकर नाबाद रहे। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड ने 3 विकेट पर 198 रन बनाए थे। सलामी बल्लेबाज एलन ने 25 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 40 रन की पारी खेली।

फिलिप्स ने 17 रन बनाए। मिचेल और जैकब्स ने 48 गेंदों पर 75 रन की साझेदारी करके कीवी टीम का स्कोर 3 विकेट पर 198 तक पहुंचाया। मिचेल ने 52 गेंदों पर 5 चौकों और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 89 रन और जैकब्स ने 23 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 39 रन बनाए।

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से निसांका बाहर, श्रीलंका ने लाहिरू उदारा को दिया मौका

कोलंबो (एजेंसी)

पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज से पहले श्रीलंका को बड़ा झटका लगा है। टीम के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका चोट की वजह से टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। पथुम निसांका बाई हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर रहे हैं।

निसांका की जगह श्रीलंका की टीम में लाहिरू उदारा को शामिल किया गया है। श्रीलंका क्रिकेट ने मंगलवार को इसकी पुष्टि की। श्रीलंका क्रिकेट ने अपने बयान में कहा, पथुम निसांका पाकिस्तान के खिलाफ आने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। वह अभी तक अपनी बाई हैमस्ट्रिंग की चोट से उबर नहीं पाए हैं। क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी ने उनकी जगह लाहिरू उदारा को शामिल किया है। उदारा श्रीलंका की वनडे टीम का हिस्सा होने की वजह से पहले से ही पाकिस्तान में हैं। निसांका को पूर्व घोषित टेस्ट टीम में शामिल किया गया था। हालांकि, उनका खेलना पूरी तरह से फिटनेस पर निर्भर था। उदारा के पहले से पाकिस्तान में मौजूद होने की वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लिए उनका चयन आसान हो गया। लाहिरू उदारा ने 5 टेस्ट मैचों में 1 शतक की मदद से 313 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 188 है। दो टेस्ट मैचों की यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का हिस्सा है। पहला टेस्ट 9 नवंबर से रावलपिंडी में और दूसरा टेस्ट 17 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। श्रीलंका की टीम की कप्तानी कुसल मेंडिस करेंगे।

न्यूजीलैंड ए पर किस्मत मेहरबान, इंडिया ए खराब रोशनी के कारण जीत से चूकी

लिंकन (एजेंसी)

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच खेला गया पहला अनाधिकारिक टेस्ट खराब रोशनी की वजह से ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ। खराब रोशनी की वजह से जिस समय मैच रोका गया, उस समय टीम इंडिया को जीत के लिए सिर्फ एक विकेट चाहिए था। न्यूजीलैंड-ए को जीत के लिए 313 रन का लक्ष्य मिला था। जवाब में चौथे दिन कीवियों ने अपनी दूसरी पारी में 187 रन पर नौ विकेट गंवा दिए थे।

मैच में करीब एक घंटे का समय बाकी थी, लेकिन मैच को खराब रोशनी की वजह से रोकना पड़ा और अंत में ड्रॉ के रूप में समाप्त हो गया। भारतीय टीम को खराब रोशनी का नुकसान हुआ। हाथ में आई जीत फिसल गई। मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड-ए के कप्तान रीस मारियू ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का

फैसला किया था। भारत ने अपनी पहली पारी में महज 113 रन बनाए थे। यश राठौड़ ने 44 रन की पारी खेली। वहीं, देवदत्त पडिक्कल ने 32 रन बनाए थे। न्यूजीलैंड-ए की ओर से साइमन कीन ने पांच और जैक गिब्सन ने तीन विकेट लिए।

जवाब में न्यूजीलैंड-ए की पहली पारी 317 रन पर समाप्त हुई थी। कप्तान मारियू ने 76 रन, कर्टिस हीफी ने 44 रन और डीन फॉक्स क्रॉफ्ट ने 51 रन की पारी खेली। क्रिश्चियन क्लार्क ने 42 रन बनाए। भारत-ए की ओर से अंशुल कंबोज और आकिब नबी ने तीन-तीन विकेट लिए। वहीं, आकाश दीप को दो विकेट मिले। न्यूजीलैंड-ए को पहली पारी के आधार पर 204 रन की बढ़त हासिल थी।

भारत ने अपनी दूसरी पारी में 516 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल दोहरे शतक से चूक गए। पडिक्कल 248 गेंद में 24 चौके और तीन छक्के की मदद से 199 रन बनाकर आउट हुए। वहीं, साई सुदर्शन 91 रन बनाकर आउट हुए। यश राठौड़ ने 66 रन, वॉशिंगटन सुंदर ने 52 रन, कंबोज ने 23 रन, नबी ने 38 रन और आकाश ने 25 रन की पारी खेली। न्यूजीलैंड की ओर से गिब्सन ने तीन विकेट लिए, जबकि क्लार्क को दो विकेट मिले। 313 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 13 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे।

इसके बाद कर्टिस हीफी और डीन फॉक्सक्रॉफ्ट के बीच चौथे विकेट के लिए 78 रन की साझेदारी हुई। डीन 42 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होते ही फिर विकेटों की झड़ी लग गई। हालांकि, आखिर में खराब रोशनी ने कीवियों को बचा लिया। हीफी 90 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए चिंता की बात यह रही कि स्टार बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी दोनों ही पारियों में फ्लॉप रही।

महिला रैंकिंग : स्मृति मंधाना ने वनडे में गंवाया शीर्ष स्थान, कौन बना नंबर एक बल्लेबाज? हरमनप्रीत ने लगाई छलांग

दुबई (एजेंसी)

पूर्व भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर मंगलवार को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में दो पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गई। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो मैचों में 32 और शून्य पर आउट होने वाली कप्तान स्मृति मंधाना ने इस लचर प्रदर्शन के कारण अपना शीर्ष स्थान गंवा दिया। उनकी जगह दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वॉर्ट पहले नंबर पर काबिज हो गई हैं।

जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में हरमनप्रीत और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने शतक बनाकर अपनी टीम को तीन मैचों की सीरीज में अजेय बढ़त दिलाई थी। हरमनप्रीत ने एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार स्वर्ण पदक जीतने के बाद कप्तानी छोड़ दी थी। दीप्ति ने बल्लेबाजों की सूची में चार स्थान ऊपर 23वां स्थान हासिल कर लिया है। वह ऑलराउंडरों की

रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चौथे और गेंदबाजों की सूची में एक स्थान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गई हैं। वनडे बल्लेबाजों की सूची में भारत की युवा खिलाड़ी प्रतिका रावल ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है। वह सात पायदान ऊपर 21वें स्थान पर काबिज हो गई हैं। जिम्बाब्वे की तीन खिलाड़ी मोडेस्टर मुपाचिकवा (पांच पायदान ऊपर 39वें स्थान पर), चिपो मुगेरी-तिरिपानो (चार पायदान ऊपर 47वें स्थान पर) और बिलव्ड बिजा (16 पायदान ऊपर 56वें स्थान पर) ने भी अपनी रैंकिंग में सुधार किया है।

इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के लिए 14 सदस्यीय टीम घोषित, पीसीबी ने मुनीबा अली को सौंपी कप्तानी

कराची (एजेंसी)

पाकिस्तान ने आगामी आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2026 के लिए अपनी 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। विकेटकीपर-बल्लेबाज मुनीबा अली को टीम की कमान सौंपी गई है, जबकि आयशा जफर उपकप्तान की जिम्मेदारी निभाएंगी।

मुनीबा को फातिमा सना की गैरमौजूदगी में कप्तानी मिली है। फातिमा ऑस्ट्रेलिया की घरेलू बिग बैश लीग में अपने पहले सीजन की प्रतिबद्धताओं के कारण इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी।

मुनीबा अली संभालेंगी टीम की कमान

मुनीबा अली इससे पहले पाकिस्तान के लिए चार टी20 अंतरराष्ट्रीय और एक वनडे मुकाबले में कप्तानी कर चुकी हैं। अब उन्हें इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में टीम का नेतृत्व करने की

जिम्मेदारी दी गई है। आयशा जफर उपकप्तान के रूप में उनकी मदद करेंगी। टीम के बल्लेबाजी समूह में ईमान नसीर, ईमान फातिमा, सदफ शमास, सायरा जबीन, शवाल जुल्फिकार और गुल फिरोजा शामिल हैं। गुल फिरोजा को हाल ही में पाकिस्तान में आयोजित राष्ट्रीय महिला टी20 टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर-बल्लेबाज चुना गया था। वह टीम को विकेटकीपिंग के लिए एक और विकल्प देंगी।

स्पिन और तेज गेंदबाजी में इन खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी

पाकिस्तान की गेंदबाजी की अगुआई नशरा संधू करेंगी। स्पिन विभाग में उनके साथ मोमिना रियासत, तुबा हसन और उम्म-ए-हानी शामिल हैं। इस तरह टीम के पास चार स्पिन विकल्प हैं। तेज गेंदबाजी में तस्मिया रुबाब और वहीदा अख्तर प्रमुख गेंदबाज होंगी। टीम का संयोजन बल्लेबाजी, स्पिन और तेज गेंदबाजी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश को दर्शाता है। महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी के पिछले संस्करण में थाईलैंड ने खिताब जीता था। पिछली बार टूर्नामेंट में आठ टीमों ने हिस्सा लिया था, जबकि 2026 के संस्करण में कुल 10 टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी।

पाकिस्तान की महिला टीम ने हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता था। अब टीम इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के इरादे से उतरेगी।

पाकिस्तान की 14 सदस्यीय टीम: मुनीबा अली (कप्तान), आयशा जफर (उपकप्तान), ईमान नसीर, ईमान फातिमा, गुल फिरोजा, मोमिना रियासत, नशरा संधू, सदफ शमास, सायरा जबीन, शवाल जुल्फिकार, तस्मिया रुबाब, तुबा हसन, उम्म-ए-हानी, वहीदा अख्तर।

तिलक वर्मा में दिखी धोनी और युवराज वाली कौन सी खासियत? सुरेश रैना ने किया खुलासा

वेलिंगटन (एजेंसी)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में भारत की रोमांचक जीत के बाद युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की जमकर तारीफ की है। रैना को तिलक में पूर्व भारतीय दिग्गजों एमएस धोनी और युवराज सिंह जैसी खूबियां नजर आती हैं। उन्होंने कहा कि तिलक में मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने वाले इन दोनों खिलाड़ियों जैसी खासियत है।

रैना ने नीतीश कुमार रेड्डी के सकारात्मक रवैये और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की वापसी की भी सराहना की। भारत ने शनिवार को क्राइस्टचर्च में खेले गए दूसरे टी20 में न्यूजीलैंड के 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए एक गेंद शेष रहते जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज में 2-0

की बढ़त बना ली। रैना ने तिलक वर्मा की तारीफ करते हुए अपने खेल के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि मध्यक्रम में बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों की भूमिका कितनी अहम होती है और तिलक में उन्हें वैसी ही मानसिकता दिखाई देती है।

रैना ने कहा, 'भारत इस समय बहुत अच्छा कर रहा है। तिलक वर्मा को ही देख लीजिए। जब युवी पा (युवराज सिंह), धोनी भाई (एमएस धोनी) और मैं पांचवें, छठे, सातवें और आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे, तो हमारे अंदर एक खास जुनून था। मुझे लगता है कि तिलक में भी वही खूबी है। उनकी सोच अलग है और उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है। वह गेंद से भी योगदान दे रहे हैं।' तिलक ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दबाव की स्थिति में जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे रैना प्रभावित नजर आए। मध्यक्रम में तेजी से रन बनाने के साथ पारी को संभालने की क्षमता टी20 क्रिकेट में काफी महत्वपूर्ण होती है। रैना के मुताबिक, तिलक की सोच और खेल के प्रति उनका नजरिया उन्हें खास बनाता है। दूसरे टी20 में भारत को जीत के लिए अंतिम पांच ओवर में 68 रन की जरूरत थी।

ऐसे मुश्किल लक्ष्य के सामने तिलक और नीतीश ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 30 गेंदों में नाबाद 69 रन की साझेदारी कर दी। दोनों ने भारत को एक गेंद शेष रहते जीत दिला दी। अंतिम पांच ओवर में बनाए गए 68 रन टी20 अंतरराष्ट्रीय में इस चरण के दौरान भारत का सबसे बड़ा सफल रन चेज रहे। टीम ने 2022 टी20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में बनाए गए अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। उस मुकाबले में विराट कोहली की नाबाद 82 रन की पारी ने भारत को यादगार जीत दिलाई थी। रैना ने नीतीश कुमार रेड्डी की बल्लेबाजी के अंदाज को भी सराहा।

ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम का शेड्यूल बेहतर बनाया जाए : एलिसा हीली

नई दिल्ली (एजेंसी)

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम दुनिया की सफलतम टीमों में से एक है, लेकिन इस टीम को अपने ही देश में वो पहचान और सम्मान नहीं मिल रहा, जिस पहचान और सम्मान की यह टीम हकदार है। पूर्व कप्तान एलिसा हीली और पूर्व क्रिकेटर मेल जोन्स ने इसको लेकर चिंता जताई है।

दरअसल, पिछले गुरुवार को नॉर्थ सिडनी ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम का तीसरा वनडे मैच खेला जाना था। उसी दिन शाम 7 बजे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुरुष टीम का टेस्ट मैच भी था। दोनों मैचों का समय टकरा गया। सिडनी में बारिश के कारण

महिला टीम का मैच सिर्फ 16 गेंदों के बाद ही रद्द करना पड़ा। इस पर एलिसा हीली ने कहा, वे शाम 7:15 बजे नॉर्थ सिडनी में खेल रहे हैं और 7 बजे टेस्ट शुरू होगा। हम अपनी ही टीम से टकरा रहे हैं, जो विदेश में खेल रही है। यह बहुत निराशाजनक है। हमारी लड़कियां इतना अच्छा खेल रही हैं, लेकिन अपने ही देश में उन्हें स्पॉटलाइट नहीं मिल रही। मेल जोन्स ने हीली की बात का समर्थन करते हुए कहा, दुनिया की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स टीम हमारे दरवाजे पर है, लेकिन हम उसे दिखा नहीं पा रहे। उनके शानदार प्रदर्शन और उनकी कहानियों को वो जगह नहीं मिल रही, जिसकी वो हकदार हैं। फैंस के लिए भी ऐसी गर्मी में आकर टीम को सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। शेड्यूल की समस्या सिर्फ एक मैच की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम अगले चार महीने तक अपने देश में कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेगी।

अक्टूबर में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज सिर्फ ब्रिस्बेन और सिडनी में ही होंगी। हीली ने कहा, आप तीन वनडे ब्रिस्बेन में और तीन टी20 सिडनी में खेल रहे हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया को उस टीम को देखने का मौका भी नहीं मिल रहा, जो अभी वर्ल्ड कप जीतकर आई है। यह सच में दुख की बात है। दरअसल, विमेंस प्रीमियर लीग, विमेंस बिग बैश लीग और आईसीसी की विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी के 2027 तक टलने से कैलेंडर काफी व्यस्त हो गया है। जोन्स ने इस विषय पर कहा, शेड्यूल का असर नेशनल टीम पर नहीं पड़ना चाहिए।

शेड्यूलिंग क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत सारे मैच एक साथ हो रहे हैं। लेकिन आपको ऊपर से शुरुआत करनी होगी। आपकी दो प्रीमियर टीमें हैं - पुरुष और महिला। यह पक्का करना होगा कि ऐसे हालात दोबारा न बनें। पुरुषों का टेस्ट शेड्यूल भी काफी देर से फाइनल हुआ था, जिसकी भी आलोचना हुई।

विराट कोहली ने हैरी केन को 'बैलन डी'ओर' के लिए दी बधाई, कहा- आप इस सम्मान के हकदार हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)

भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने इंग्लैंड के फुटबॉल कप्तान हैरी केन को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर अवॉर्ड से सम्मानित होने पर बधाई दी है। विराट ने कहा कि केन इस अवॉर्ड के हकदार हैं। कोहली ने एक्स पर लिखा, 'हैरी मेरे दोस्त, इतने सालों तक टॉप पर फुटबॉल खेलते हुए जिस लगन, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से तुमने खुद को संभाला है, उसके लिए तुम इस अवॉर्ड के हर तरह से हकदार हो। तुम्हारे लिए सच में बहुत खुश हूं। भगवान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद दें। वे

सभी तुम पर बहुत गर्व करते होंगे, जैसे तुम्हें अपने सफर पर गर्व होता होगा। मेरी शुभकामनाएं हमेशा।

बधाई हो।' इंग्लैंड के कप्तान ने फ्रांस के काइलियन एम्बाप्पे और स्पेन के लामिन यामाल जैसे खिलाड़ियों को हराकर यह प्रतिष्ठित अवॉर्ड जीता। केन को यह अवॉर्ड लंदन पैलेडियम थिएटर में हुए समारोह में दिया गया। वह सर स्टेनली मैथ्यूज (1956), सर बॉबी चार्लटन (1966), केविन कीगन (1978 और 1979), माइकल ओवेन (2001) के बाद यह अवॉर्ड जीतने वाले सिर्फ पांचवें अंग्रेज खिलाड़ी हैं। केन पिछले 25 साल में बैलन डी'ओर का खिताब पाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी हैं। केन ने 2025/26 में बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख के लिए 36 गोल किए, जिससे स्ट्राइकर को दूसरा यूरोपियन गोल्डन शू मिला, जबकि जर्मन जायंट के लिए सभी कॉम्पिटिशन में उनके 61 गोल ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरीं। उन्हें गर्ड मुलर ट्रॉफी भी मिली, जो साल के बेस्ट मेन्स स्ट्राइकर को दी जाती है।

साउथ एक्सेंट पर ट्रोलिंग को लेकर बोलीं ईशा देओल, कहा-मुझे तो बहुत क्यूट लगता है

अभिनेत्री ईशा देओल 15 साल बाद एक्शन-क्राइम ड्रामा फिल्म 'प्रताप' से बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। अभिनेत्री ने बातचीत में साउथ इंडियन एक्टर्स के एक्सेंट को लेकर ट्रोल किए जाने पर प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री का कहना है कि उन्हें साउथ इंडियन एक्सेंट काफी 'प्यारा' और 'क्यूट' लगता है। ईशा ने कहा, जब मैं अपने डायलॉग बोलती हूं, खासकर हिंदी में, तो मैं काफी हद तक अपनी मां जैसी लगती हूं, लेकिन असल में मैं वैसी ही हूं और जिन्होंने मुझे किसी खास किरदार के लिए लिया है, वो ये बात अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ इंडियन लोगों का हल्का-सा एक्सेंट सुनना बहुत प्यारा और क्यूट लगता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभिनेत्री ने आगे बताया कि बॉलीवुड में भी ऐसी कई दिग्गज अभिनेत्रियां हैं, जिनकी बोली में साउथ इंडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है। उन्होंने कहा, और भी कुछ लोगों जैसे श्री आंटी, मेरी मम्मी और उर्मिला में भी साउथ इंडियन एक्सेंट सुनने को मिलता है। उर्मिला की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूं और उनकी बोली में जो हल्का-सा एक्सेंट आता है, वो मुझे पसंद है। अभिनेत्री ने आगे कहा कि लोगों के बोलने के तरीके का मजाक उड़ाने के बजाय भाषाई और सांस्कृतिक विविधता की सराहना करना जरूरी है। दरअसल, साउथ इंडियन एक्सेंट को लेकर चर्चा तब तेज हो गई जब अभिनेत्री रश्मिका मंदाना ने करण जौहर के टॉक शो 'कॉफी विद करण सीजन 9' में अपने साउथ इंडियन एक्सेंट को लेकर होने वाली ट्रोलिंग पर खुलकर बात की थी। इस एपिसोड में रश्मिका अपने पति और अभिनेता विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई थीं। शो के दौरान रश्मिका ने कहा कि वे दक्षिण भारत से हैं, इसलिए उनके बोलने के लहजे में वहां की झलक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रश्मिका ने यह भी बताया कि वे अपनी फिल्मों के लिए खुद अलग-अलग भाषाओं में डबिंग करने में गर्व महसूस करती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ट्रोलिंग उन्हें अपना काम करने से नहीं रोक सकती। **(एजेंसी)**

कीर्ति सुरेश : नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली अभिनेत्री ने क्यों नहीं की बॉलीवुड में आने की जल्दबाजी?

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश इन दिनों अपनी आने वाली सीरीज 'अक्का' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। इस सीरीज में वह अभिनेत्री राधिका आप्टे के साथ दिखाई देंगी। बता दें कि साउथ अभिनेत्री कीर्ति ने 2024 में वरुण धवन स्टारर फिल्म 'बेबी जॉन' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में आने और काम करने को लेकर बात की। कीर्ति ने बताया कि वह हिंदी सिनेमा में काम करना चाहती थीं, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। वह चाहती थीं कि सब कुछ सही समय पर अपने आप हो।

क्या बोलीं कीर्ति सुरेश?

कीर्ति ने पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'मैं निश्चित रूप से किसी समय हिंदी सिनेमा में काम करना चाहती थी और आखिरकार ऐसा हुआ। इसकी शुरुआत 'अक्का' से हुई। इस बीच 'बेबी जॉन' आई और उसके बाद मैंने राजकुमार राव के साथ 'रफ्तार' नाम की फिल्म की। यह फिल्म भी जल्द रिलीज होनी चाहिए।' अभिनेत्री ने आगे कहा, 'मैं किसी रेस में नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारी फिल्में करनी हैं। मैं वही काम कर रही हूं जो मुझे पसंद है। हिंदी सिनेमा में काम करने का मौका भी मुझे इसी तरह मिला। मैं इसके पीछे भाग नहीं रही थी। सब कुछ अपने आप सही समय पर हुआ और अब देखूंगी कि इसे आगे कैसे बढ़ाना है।'

कैसे कीर्ति को मिली 'अक्का'?

कीर्ति ने बताया कि धर्मा (निर्देशक) ने मेरी फिल्म 'सानी कायिधम' देखी थी। उसमें मेरा किरदार बेहद मजबूत और बेखौफ था, लेकिन उसके अंदर एक संवेदनशील पहलू भी था। मुझे हमारी पहली मुलाकात याद है। उन्होंने बताया कि उन्होंने यह फिल्म देखी है। तब मैंने उनसे कहा कि अब मैं समझ गई कि आप मुझे यह किरदार क्यों देना चाहते हैं।

क्या है 'अक्का' की कहानी?

कीर्ति और राधिका स्टारर 'अक्का' की कहानी 1980 के दशक में पेरनुरु नाम के एक काल्पनिक राज्य में दिखाई गई है, जहां महिलाओं का दबदबा है। फिल्म की कहानी भवानी (कीर्ति) और रुद्रा (राधिका) नाम की दो ताकतवर महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है। दोनों की अलग-अलग सोच और उनके बीच की दुश्मनी राज्य में सत्ता के समीकरण तय करती है।

कब रिलीज होगी 'अक्का'?

- 'अक्का' का निर्देशन धर्मराज शेट्टी ने किया है।
- सीरीज में कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे के अलावा तन्वी आजमी, महेश मांजरेकर, अंशुमान पुष्कर और मोनिका पंवार समेत कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। **(एजेंसी)**

पूजा बत्रा बर्थडे स्पेशल : कल्पना चावला से प्रेरित होकर बनीं 'अंतरिक्ष यात्री', अब हॉलीवुड में फिल्म निर्माण से जुड़ीं

बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग और फिल्मों से की, लेकिन कुछ समय बाद उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वे फिल्मी पर्दे से दूर हो गईं। पूजा बत्रा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद उन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान बनाई और फिर निजी जिंदगी के फैसलों के चलते कुछ समय के लिए हिंदी सिनेमा से दूरी बना ली। इसके बाद उन्होंने विदेश में अपनी जिंदगी और करियर को नए सिरे से आगे बढ़ाया। इस रोल की तैयारी के लिए उन्होंने भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के जीवन के बारे में भी पढ़ा। अब पूजा अभिनय के साथ फिल्म निर्माण की दुनिया में भी सक्रिय हैं। पूजा बत्रा का जन्म 27 अक्टूबर 1975 को हुआ था। उनके पिता रवि बत्रा भारतीय सेना में कर्नल थे, जबकि उनकी मां नीलम बत्रा ने भी 1971 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। सेना में पिता की नौकरी के कारण पूजा को बचपन में अलग-अलग जगहों पर रहना पड़ा। उन्होंने करीब 12 साल में 10 स्कूल बदले। बचपन से ही उन्हें खेलों में दिलचस्पी थी और वह दौड़ की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती थीं। पूजा ने कम उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दी थी। एक साबुन के विज्ञापन से उन्हें काफी पहचान मिली। साल 1993 में उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता। इस उपलब्धि के बाद उनके लिए मनोरंजन की दुनिया में नए रास्ते खुले। हालांकि, उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की और इसके बाद फिल्मों में कदम रखा। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'विरासत' से उन्होंने हिंदी सिनेमा में पहचान बनाई। इस फिल्म में वह अनिल कपूर और तब्बू के साथ नजर आईं। इसके बाद उन्होंने 'भाई', 'हसीना मान जाएगी', 'दिल ने फिर याद किया', 'कहीं प्यार न हो जाए' और 'नायकः द रियल हीरो' जैसी फिल्मों में काम किया। पूजा की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया, जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने अमेरिका में रहने वाले ऑर्थोपेडिक सर्जन सोनू एस. अहलूवालिया से शादी की और लॉस एंजिलिस में रहने लगीं। बाद में दोनों का तलाक हो गया। इस बदलाव के बाद पूजा ने अपने जीवन और करियर को फिर से आगे बढ़ाने पर ध्यान दिया। उन्होंने भारतीय फिल्मों के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में भी मौके तलाशे। पूजा के करियर का एक खास पड़ाव 2016 में आई साइंस-फिक्शन फिल्म 'वन अंडर द सन' रही। इस फिल्म में उन्होंने कैथरीन वॉस नाम की अंतरिक्ष यात्री का किरदार निभाया था। कहानी एक ऐसे अंतरिक्ष मिशन की अकेली बची यात्री के बारे में थी, जो धरती पर लौटने के बाद अपनी बीमार बेटी से मिलना चाहती है। **(एजेंसी)**

50 साल की महिला बनने के लिए वामिका गब्बी ने पहना प्रोस्थेटिक्स, बोलीं- शीशे में खुद को पहचान नहीं पाई

अभिनेत्री वामिका गब्बी ने फिल्म 'प्रहार- द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' में प्रसिद्ध सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की पत्नी ज्योति निकम के किरदार निभाया है। अभिनेत्री ने किरदार निभाने के लिए प्रोस्थेटिक्स पहनने के अपने अनुभव को साझा किया। अभिनेत्री ने बताया कि मेकअप चेयर पर बैठे-बैठे अपने चेहरे को बदलते हुए देखना किरदार को और भी ज्यादा वास्ताविक महसूस करा रहा था। उन्होंने कहा, प्रोस्थेटिक्स के बाद जब मैंने खुद को शीशे में देखा, तो कुछ देर तक तो मैं शीशे में खुद को निहारती रह गई। ये एक बहुत ही अजीब एहसास था, क्योंकि मुझे पता था कि वो मैं ही हूँ, लेकिन मैं सामने दिख रहे शख्स को पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि, इस पूरे प्रोसेस को मैंने पूरी तरह से इंजॉय किया था। अभिनेत्री ने आगे कहा, मेकअप चेयर पर बैठने के बाद चेहरे को धीरे-धीरे बदलते हुए देखने पर कहीं न कहीं किरदार आपके लिए और ज्यादा असली लगने लगता है। कई बार तो मैं भूल ही जाती थी कि मैं कितनी अलग दिख रही हूं, जब तक कोई मुझे सेट से मेरी फोटो नहीं दिखा देता था। वामिका गब्बी ने बताया कि ज्योति निकम का किरदार निभाना उनके लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा, ज्योति निकम का किरदार निभाना मेरे लिए एक बहुत ही अलग अनुभव था और मुझे खुशी है कि मुझे एक्टिंग के उस पहलू को एक्सप्लोर करने का मौका मिला, जिसे मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ज्योति निकम का किरदार उज्ज्वल निकम (राजकुमार राव द्वारा निभाया गया किरदार) के पेशेवर और निजी जीवन के बीच के तालमेल को दर्शाता है। **(एजेंसी)**

भारत में निवेश और चिप निर्माण के बड़े अवसर, डच कंपनियों को पीयूष गोयल ने दिया न्योता

नई दिल्ली (एजेंसी)

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीदरलैंड्स की कंपनियों को भारत में निवेश, सह-विनिर्माण (को-मैन्युफैक्चरिंग) और नवाचार के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, सुधारों की गति और तेजी से विकसित हो रहा विनिर्माण एवं प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र डच कंपनियों के लिए व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है।

नीदरलैंड्स में आयोजित बिजनेस लीडर्स राउंडटेबल के दौरान गोयल ने कई प्रमुख कंपनियों के मुख्य अधिकारियों और उद्योग नेताओं के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने भारत की विकास यात्रा, निवेश संभावनाओं और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर प्रकाश डाला। गोयल ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए नेक्सपेरिया के अंतरिम सीईओ स्टीफन टिल्गर से मुलाकात की। उन्होंने एक्स पोस्ट में कहा, भारत की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता और विस्तार करते तकनीकी इकोसिस्टम के कारण वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने इंग्का ग्रुप (आईकेईए) के सीईओ और अध्यक्ष जुवेंसियो माएज्तु के साथ भी बैठक की। इस दौरान भारत के बढ़ते उपभोक्ता बाजार और देश की मजबूत विनिर्माण क्षमताओं पर चर्चा हुई।

गोयल ने कहा कि आईकेईए भारत को अपने वैश्विक सोर्सिंग नेटवर्क के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित कर सकता है। दोनों पक्षों ने कंपनी की भारत में मौजूदगी और निवेश को और विस्तार देने की संभावनाओं पर भी विचार किया।

इसके अलावा, गोयल ने पावर2एक्स के संस्थापक एवं सीईओ ओको रूएलोफसेन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत-नीदरलैंड्स सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और हरित विकास के साझा लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर गोयल की एक महत्वपूर्ण बैठक एएसएमएल के कार्यकारी उपाध्यक्ष और बोर्ड सदस्य वेन एलन के साथ भी हुई। उन्होंने भारत में सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एएसएमएल की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया।

दिवाली से पहले खरीदारों की मौज, सोना-चांदी हुआ और सस्ता, उच्चतम स्तर से गोल्ड 50.7 हजार तो चांदी 2.28 लाख रुपए के नीचे

नई दिल्ली (एजेंसी)

धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कई दिनों से जारी गिरावट के बीच मंगलवार को भी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कीमती धातुओं पर दबाव बना रहा। घरेलू बाजार एमसीएक्स पर सोने में 0.43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, और यह 1.42 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया। वहीं चांदी 2.1 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1.91 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई। इस तरह, सोने और चांदी की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तरों से काफी नीचे आ चुकी हैं, जिससे त्योहारी खरीदारी की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। बाजार जानकारों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर ऊंची ब्याज दरों की आशंका, कमजोर निवेश मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जारी बिकवाली का असर घरेलू कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, कॉमेक्स में मंगलवार को सोना करीब 0.54 प्रतिशत गिरकर 4,016.60 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया, जबकि चांदी 2.73 प्रतिशत की गिरावट के साथ 52.855 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। पिछले कुछ हफ्तों से वैश्विक बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है और सोना मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। निवेशकों की नजर अब अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और आगे की ब्याज दर नीति पर बनी हुई है। वहीं, वैश्विक कमजोरी का असर भारतीय बाजार में भी दिखा।

टाटा संस में नेतृत्व विवाद फिर गहराया, नोएल टाटा ने चेयरमैन पद पर चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को दी चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)

टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में नेतृत्व को लेकर विवाद गहराता दिखाई दे रहा है। नोएल टाटा ने कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देते हुए दावा किया है कि इस फैसले में कई प्रक्रियागत खामियां हैं और संभावित हितों के टकराव से जुड़े सवालों को नजरअंदाज किया गया है। कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को भेजे गए एक पत्र में नोएल टाटा ने सात दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है

कि जिस प्रस्ताव के जरिए चंद्रशेखरन को 21 फरवरी 2027 से अगले पांच वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया, वह वैध नहीं माना जा सकता।

नोएल टाटा का आरोप है कि बोर्ड बैठक के मूल एजेंडे और संशोधित एजेंडे दोनों में कार्यकारी चेयरमैन की पुनर्नियुक्ति से संबंधित किसी प्रस्ताव का स्पष्ट उल्लेख नहीं था। उनके अनुसार एजेंडा के आइटम-7 को केवल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की रिपोर्ट या चर्चा के रूप में दर्शाया गया था, लेकिन इसी बिंदु के तहत पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समिति की बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त (मिनट्स) निदेशकों के बीच पहले से साझा नहीं किए गए थे, जिससे निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। नोएल टाटा ने टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का हवाला देते हुए यह भी पूछा है कि चेयरमैन के चयन के लिए आवश्यक चयन समिति का गठन क्यों नहीं किया गया।

व्यापारियों ने राहुल गांधी के रैली पर फिर उठाई तारीख बदलने की मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)

दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने एक बार फिर 1 नवंबर को प्रस्तावित इंडिया गठबंधन की रैली को स्थगित करने की मांग उठाई है। यह मांग ऐसे समय सामने आई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर स्पष्ट कर दिया है कि रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को आयोजित करने का इरादा बरकरार है। सीटीआई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र की प्रति भेजते हुए अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगी दलों से चर्चा करें। व्यापारियों का कहना है कि प्रस्तावित

रैली दिवाली के पहले चल रहे सबसे महत्वपूर्ण खरीदारी सीजन के बीच आयोजित की जा रही है, जिससे दिल्ली के कारोबार पर गंभीर असर पड़ सकता है। सोमवार को राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में दिल्ली के व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा था, हम आपको सुनते हैं और आपकी परवाह करते हैं। सरकार ने मेट्रो बंद कर दी, सड़कें सील कर दीं और राजधानी को लॉकडाउन जैसा बना दिया। अगर मोदी आरोपित नंबर-4 ज्ञानेश कुमार को हटा दें तो विरोध प्रदर्शन 30 सेकंड में खत्म हो सकते हैं। हालांकि सीटीआई का कहना है कि इस बयान से व्यापारियों की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं। संगठन के चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार, रामलीला मैदान के आसपास स्थित 20 प्रमुख बाजारों के व्यापारी रैली की घोषणा के बाद बेहद चिंतित हैं और व्यापारिक समुदाय में असमंजस तथा भय का माहौल है। व्यापारियों ने सवाल उठाया है कि क्या 31 अक्टूबर से ही बैरिकेडिंग शुरू कर दी जाएगी, क्या राजधानी के कई प्रमुख मार्ग बंद होंगे और क्या ग्राहकों को बाजारों तक पहुंचने में कठिनाई होगी। उनका कहना है कि यदि कांग्रेस नेताओं का यह अनुमान सही है कि रैली में 10 लाख लोग और 15,000 से 20,000 वाहन शामिल होंगे, तो इतनी बड़ी संख्या में वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कहां होगी। सीटीआई ने कहा है कि रामलीला मैदान के आसपास 200 वाहनों के लिए भी अधिकृत पार्किंग उपलब्ध नहीं है, जबकि यह क्षेत्र दिल्ली के सबसे बड़े थोक और खुदरा बाजारों से घिरा हुआ है। संगठन का दावा है कि रैली से करीब 21 प्रमुख बाजार सीधे प्रभावित होंगे। व्यापारियों के संगठन ने यह भी याद दिलाया कि 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आयोजित एक प्रदर्शन, जिसमें केवल 3,000 से 4,000 लोग शामिल हुए थे, उसके कारण मध्य दिल्ली के बड़े हिस्से में यातायात प्रतिबंध लगाए गए थे और व्यापारियों को लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। सीटीआई का कहना है कि यदि 1 नवंबर को 10 लाख लोगों की रैली आयोजित होती है तो पुरानी दिल्ली और मध्य